

आज

बेबाक

जिस देश में भ्रष्टाचार ने शिक्षाचार का रूप ले रखा हो वहां किसी सरकारी कारिंदे के पास से लाखों करोड़ों की बरामदगी ताज्जुब की बात नहीं है। एक अदना सा सरकारी कर्मचारी भी जहां करोड़ों का आसामी निकलता हो वहां हाईकोर्ट के किसी जज के यहां करोड़ों मिलना हैरत की बात नहीं है। आखिर वे भी ईसान है उनकी भी अपनी जरूरतें हैं। बुढ़ापे के लिए चार पैसे जोड़ लिये तो कौन सा पहाड़ टूट गया? बकील एक शायर कुछ तो मजबूरियां रही होगी उनकी यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। इसलिए जलों मत बराबरी करो।

सैन्य सहयोग का दायरा बढ़ाएंगे भारत और इटली

नयी दिल्ली (वार्ता)। भारत और इटली ने सैन्य सहयोग का दायरा बढ़ाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए गहन विचार विमर्श किया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत-इटली सैन्य सहयोग समूह की रोम में शुक्रवार को 13वाँ बैठक में संपन्न हुई। दो दिन की इस बैठक की सह-अध्यक्षता एकीकृत रक्षा स्टाफ (मुख्यालय आईडीएस) के उप सहायक एकीकृत रक्षा स्टाफआईडीसी (ए) और इटली के रक्षा जनरल स्टाफके सामरिक और सैन्य सहयोग प्रभाग के उप प्रमुख ने की। दोनों पक्षों के बीच यह चर्चा द्विपक्षीय सैन्य केंद्रित सहयोग के दायरे का विस्तार करने के लिए नए रास्ते तलाशने पर केंद्रित थी। प्रमुख एजेंडा बिंदुओं में भारतीय और इटालीय सशस्त्र बलों के बीच बेहतर आदान-प्रदान कार्यक्रम, क्षमता विकास के प्रयास और परस्पर सहयोग को मजबूत करना शामिल था। बैठक में रक्षा संबंधों की समीक्षा के साथ-साथ प्रगति का आकलन किया गया और भविष्य की बातचीत के तरीकों पर मंथन किया गया। भारत-इटली सैन्य सहयोग समूह दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने, मजबूत सैन्य संपर्क और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख संस्थागत तंत्र के रूप में कार्य करता है।

ओबीसी आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई

जबलपुर। बहुचर्चित ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में शनिवार को सुनवाई हुई। सॉलिडिस्टर जनरल ने कहा कि आगामी भर्तियां कानून संपात होगी। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने दलील दी कि मध्यप्रदेश में ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण पर रोक नहीं है। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण संबंधित कानून को कभी चैलेंज नहीं किया गया। भर्ती संबंधित नोटिफिकेशन (विज्ञापन) को चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराई बात कि- मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ओबीसी आरक्षण से संबंधित किसी भी प्रकरण को सुनवाई नहीं करेगा। ओबीसी आरक्षण के पक्ष या विपक्ष में किसी भी याचिका की सुनवाई मध्यप्रदेश हाईकोर्ट नहीं करेगी। ओबीसी से जुड़ी नई याचिका सीधे सुप्रीम कोर्ट में लगा सकेगे। हाइकोर्ट में नई याचिका लगने पर भी सुनवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से स्पष्ट है कि कानून के अनुसार भर्तियां करने में कोई बाधा नहीं है। ऑर्डर अपलोड होने का इंतजार किया जा रहा है। ऑर्डर आने पर बाकी स्थिति क्लियर होगी।

शाह से मिले सुखू, मुआवजा राशि जारी करने का किया आग्रह

नयी दिल्ली (वार्ता)। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखचिंद सिंह सुखू ने शनिवार को यहां केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट करके आमदा से हुए नुकसान के लिए मुआवजे की राशि जारी करने का आग्रह किया। हिमाचल प्रदेश सरकार की आधिकारिक सूचना के अनुसार, मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री से वर्ष 2023 के मानसून में भीषण प्राकृतिक आपदा के दौरान प्रदेश को हुए भारी नुकसान के लिए मुआवजा जारी करने का आग्रह किया।

राज्य सरकार ने आपदा उपरांत आवश्यकता मूल्यांकन वित्तीय सहायता प्रदान करने का केंद्र से अनुरोध किया है लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक राहत राशि प्रदान नहीं की गई है।

मध्यप्रदेश सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी बनने की ओर अग्रसर : सीएम यादव

नवकरणीय ऊर्जा में 5.72 लाख करोड़ से अधिक का निवेश

सृजित होंगे 1.4 लाख से अधिक रोजगार के अवसर

भोपाल/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 32 गुना बढ़ी है, जिससे भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। उन्होंने वर्ष 2030

तक कुल नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन 500 गीगावाट तक करने का लक्ष्य तय किया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के विजन को साकार करने मध्यप्रदेश सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नया इतिहास रच रहा है। प्रदेश की नवकरणीय ऊर्जा क्षमता पिछले एक दशक में 14 गुना से अधिक बढ़ी है। राज्य सरकार की ठोस नीतियां, निवेश अनुकूल माहौल और तकनीकी नवाचार इसे ‘सूर्य देव का वरद प्रदेश’ बना रहे हैं।

जीआईएस-भोपाल में मध्यप्रदेश की टेक्नोलॉजी एनोस्टिक रिन्यूएबल



एनजी पॉलिसी के कारण नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भारी निवेश प्रस्ताव प्राप्त

हुए हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जीआईएस-भोपाल के उद्घाटन अवसर पर कहा कि विगत दशक में भारत के ऊर्जा क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में 70 बिलियन डॉलर (5 ट्रिलियन रुपये से अधिक) का निवेश हुआ है। इससे स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में 10 लाख से अधिक रोजगार सृजित हुए। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस विकास में मध्यप्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया और

बताया कि मध्यप्रदेश वर्तमान में लगभग 31,000 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता रखता है, जिसमें से 30व हरित ऊर्जा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि सौर ऊर्जा भविष्य की अर्थव्यवस्था का केंद्र बनेगी। मध्यप्रदेश ने अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्तमान में राज्य की कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता राज्य की कुल ऊर्जा क्षमता का लगभग 21 प्रतिशत है।

मध्यप्रदेश सरकार नवकरणीय

ऊर्जा क्षेत्र में 5,21,279 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित कर रही है, जिससे 1,46,592 नौकरियाँ सृजित होंगी। जीआईएस-भोपाल में नवकरणीय ऊर्जा सेक्टर में अवाडा एनर्जी, एमकेसी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, एक्सिस एनर्जी वेंचर, एनएसएल रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड, टोरेट पावर और ज़िंदल इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों ने निवेश प्रस्ताव दिए हैं। इस निवेश से राज्य में अक्षय ऊर्जा उत्पादन **शेष पृष्ठ 5 पर**

सम्राट विक्रमादित्य के जीवन और शासन व्यवस्था से जन-जन को अवगत कराना है विक्रमोत्सव का उद्देश्य : सीएम यादव

राष्ट्रपति मुर्मु, प्रधानमंत्री मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री शाह को मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किया आमंत्रित

विक्रमोत्सव के 12-13-14 अप्रैल को नई दिल्ली में होंगे कार्यक्रम

भोपाल/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी भारतीय ज्ञान परम्परा से «विरासत से विकास»’ के ध्येय को देश में साकार कर रहे हैं। भगवान श्रीराम के बाद सम्राट विक्रमादित्य का शासन ही सुशासन की मिसाल स्थापित करता है। प्रदेश सहित देश के विभिन्न भागों में विक्रमोत्सव अंतर्गत हो रहे कार्यक्रम सम्राट विक्रमादित्य के जीवन के विभिन्न पहलुओं और उनकी शासन व्यवस्था से जन-जन को प्रेरित करने का एक अभूतपूर्व प्रयास है। आगामी 12-13 और 14 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में सम्राट विक्रमादित्य पर केन्द्रित भव्य आयोजन होने जा रहा है। इसमें राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु, प्रधानमंत्री श्री मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह को आमंत्रित किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विक्रमोत्सव के संबंध में नई दिल्ली में मीडिया के लिए जारी संदेश में ये विचार व्यक्त किए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि न्यायप्रियता, ज्ञानशीलता, धैर्य,



पराक्रम, पुरुषार्थ, वीरता और गंभीरता जैसी विशेषताओं के लिए सम्राट विक्रमादित्य का संपूर्ण भारत के साथ ही विश्व में आदर के साथ स्मरण किया जाता है। सम्राट विक्रमादित्य द्वारा अपने सुयोग्य 32 मंत्रियों का चयन किया, इसीलिए उनके सिंहासन को «सिंहासन बत्तीसी» कहा जाता है। सम्राट विक्रमादित्य ने गणराज्य की स्थापना कर लोकतांत्रिक व्यवस्था का क्रियान्वयन आरंभ किया। साथ ही जनता के लिए जवाबदेह नगरों का मंत्री-मंडल गठित कर ऐसी व्यवस्था की जिसमें राजा नहीं बल्कि नौ मंत्रियों

द्वारा लिए गए निर्णयों का शासन द्वारा क्रियान्वयन किया जाता था। सुशासन के लिए वर्तमान में क्रियावित्त मापदंड सम्राट विक्रमादित्य के काल की याद दिलाते हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सम्राट विक्रमादित्य ने शून्य प्रतिशत ब्याज पर राशि देकर व्यापार-व्यवसाय को प्रोत्साहित किया और हर व्यक्ति के लिए आशियाने की बात कही। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भी शहरी हो या गरीब सभी के लिए पक्के मकान की व्यवस्था के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। उनके द्वारा बिना ब्याज के धन राशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की गई है। शिक्षा, न्यायप्रियता प्रत्येक क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ाने के लिए सम्राट विक्रमादित्य का काल और आज के

इस काल में अनेकों समानताएं हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विक्रमोत्सव भारतीय ज्ञान परम्परा के विभिन्न पहलुओं के प्रकटीकरण का एक माध्यम है। सम्राट विक्रमादित्य का व्यक्तित्व और शासन पद्धति, विभिन्न पक्ष हैं। उनके शासन काल में प्रत्येक मंत्री अलग विषयों के विशेषज्ञ थे जो देश के अलग-अलग क्षेत्रों से आकर सम्राट विक्रमादित्य की शासन व्यवस्था से जुड़कर, व्यवस्था को सुशासन में बदलने का कार्य कर रहे थे। माना जाता है कि तीन भाईयों की जोड़ी विश्व में प्रसिद्ध है, इनमें प्रथमतः भगवान श्रीराम और लक्ष्मण की, भगवान श्रीकृष्ण और बलराम की तथा तीसरी जोड़ी सम्राट विक्रमादित्य और भूतहरि की है। यह तीसरी जोड़ी मध्यप्रदेश से है। यह सोभाया का विषय है कि सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैन रही।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गुड़ी पड़वा पर सम्राट विक्रमादित्य के जीवन चरित्र पर केन्द्रित आयोजन सम्पूर्ण प्रदेश में होंगे। राज्य के बाहर भी सम्राट विक्रमादित्य पर आधारित महानाटिका के माध्यम से उनके जन-हितेषी कार्यों की जानकारी जन-जन को देने का प्रयास किया जा रहा है। गत वर्ष हैदराबाद में इसी प्रकार का आयोजन किया गया था, यह अभियान लगातार जारी रहेगा।

‘जुग-जुग जिये बिहार’ : स्थापना दिवस पर बधाइयों का तांता



● पीएम मोदी, गृहमंत्री और राहुल गांधी सहित अन्य नेताओं ने दी बधाई

पटना । बिहार को आज उसके स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर केंद्र और

राज्य के तमाम मंत्री एवं राजनीतिक हस्तियों ने बधाई और शुभकामनाओं के साथ ही उसे जुग-जुग जीने का आशीष भी दिया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने शनिवार को सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर अपने पोस्ट में लिखा, वीरों और महान विभूतियों की पावन धरती बिहार के अपने सभी भाई-बहनों को बिहार दिवस की ढेरों **शेष पृष्ठ 5 पर**

मणिपुर में आठ उग्रवादी गिरफ्तार

इंफाल । मणिपुर पुलिस और सुरक्षाकर्मियों ने पिछले 24 घंटों के दौरान विभिन्न अभियानों में आठ उग्रवादियों को गिरफ्तार किया।

सुरक्षा बलों ने इम्फल पूर्वी जिले के एंड्रो थाना क्षेत्र के उचोल माखा लेकाई से आरपीएफ/पीएलए के एक सक्रिय कैडर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, वह आम जनता से जबरन वसूली की गतिविधियों में शामिल था। एक अन्य अभियान में, सुरक्षा बलों ने इम्फल पूर्वी जिले के पोरोमपट थाना क्षेत्र के पास खुरई चिंगंगबम लेकाई स्थित कम्युनिटी हॉल के पास से पीआरडीपीएके के एक सक्रिय कैडर को गिरफ्तार किया। वह भी आम जनता से जबरन वसूली की गतिविधियों में शामिल था। एक अलग घटना में, मणिपुर पुलिस ने इम्फल पश्चिम जिले में तीन सक्रिय कैडरों को उनके आवासों से गिरफ्तार किया। वे केसीपी (अपुनबा) संगठन से जुड़े हुए थे। पुलिस ने उनके पास से एक 9 एमएम राइफल, एक मैगजीन जिसमें तीन राउंड थे, एयर गन, डबल बैरल गन और अन्य सामान बरामद किए।

मणिपुर पुलिस ने अभियान जारी रखते हुए

कृषि की चुनौतियों के समाधान में आगे आएँ छात्र: शिवराज

नयी दिल्ली । केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शोध और नवाचार, कृषि स्टार्टअप तथा प्राकृतिक खेती पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा है कि कृषि छात्रों को भारतीय कृषि की चुनौतियों के समाधान में आगे आना चाहिए।

चौहान ने शनिवार को यहां भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) के 63वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हरित क्रांति के अग्रदूत आईएआरआई ने अपने उत्कृष्ट शोध, शिक्षा और



विस्तार गतिविधियों से कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि को निरंतर गति प्रदान की है।

इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और रामनाथ ठाकुर शामिल रहे। इस अवसर पर

गेहूं, मक्का, चना, मूंग और आम सहित विभिन्न फसलों की नयी किस्मों का विमोचन किया। साथ ही, तीन प्रमुख प्रकाशनों का भी अनावरण किया गया।

चौहान ने कहा कि भारत की कृषि विकास दर पांच प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी अनंत शक्तियों का भंडार हैं और उन्हें सकरात्मक ऊर्जा के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और किसानों की मेहनत से देश अन्न भंडारों से समृद्ध हुआ है।

गरमा-गरम

संविधान में हो संशोधन..., स्टालिन की अगुवाई में JAC का 7-सूत्रीय प्रस्ताव पास



कमलनाथ बोले- बीजेपी के कारण सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, सिंधार ने कहा- प्रतिबद्धता दिखाए सरकार

भोपाल/नवप्रदेश। प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस हमलावर है। और बीजेपी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट में इस वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिलाने के लिए तथ्यों के साथ कार्यवाही करने को कहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि बीजेपी के ओबीसी विरोधी रुख के कारण ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग

सिंधार ने कहा है कि अब सरकार इस मामले में अपनी प्रतिबद्धता दिखाए।

पूर्व सीएम कमलनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर ट्वीट कर कहा है कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार का ओबीसी विरोधी रुखा सर्वविदित है। मेरे मुख्यमंत्री कार्यकाल में सरकारी भर्तियों में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का कानून बनाया गया था। जिसे हर स्तर पर भाजपा सरकार ने लागू होने से रोकने की कोशिश की है।

अब इस विषय में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार मौजूदा कानून के तहत विज्ञापन जारी कर भर्तियां करने को



स्वतंत्र है। उससे स्पष्ट है कि आज की स्थिति तक 27 प्रतिशत ओबीसी रिजर्वेशन के कानून पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इस तरह अगर भाजपा चाहती तो पिछले पांच साल से हुई भर्तियों में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दे

सकती थी लेकिन भाजपा ने ऐसा नहीं किया।

नाथ ने कहा कि वे सरकार से मांग करते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट में पूरी जम्मेदारी के साथ ओबीसी आरक्षण को लागू करने के लिए

पैरवी करे। प्रदेश की जनता को अच्छी तरह मालूम है कि हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान भाजपा सरकार ने ओबीसी विरोधी रुख अपनाया, जिस कारण अंततः यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। अगर मध्य प्रदेश सरकार ईमानदारी और तथ्यों के साथ सुप्रीमकोर्ट में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के पक्ष में अपनी दलील रखेगी तो ओबीसी को उसके हक से वंचित नहीं होना पड़ेगा।

सिंधार का ट्वीट, अपनी प्रतिबद्धता दिखाए सरकार

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग

सिंधार ने भी इसको लेकर एक्स पर किए गए ट्वीट में कहा है कि अब ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए सरकार प्रतिबद्धता दिखाए। पूर्व सीएम कमलनाथ के कार्यकाल में ही सरकारी भर्तियों में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का कानून बनाया गया था। जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार मौजूदा कानून के तहत विज्ञापन जारी कर भर्तियां करने को स्वतंत्र है। इसका सीधा मतलब है कि अगर भाजपा चाहती तो पिछले 5 सालों से हुई भर्तियों में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण **शेष पृष्ठ 5 पर**

भाजपा ने परिसीमन विवाद को बताया डीएमके का ‘नाटक’, राज्य के अधिकार दूसरे राज्यों को देने का लगाया आरोप

नई दिल्ली। भाजपा की तमिलनाडु ईकाई ने शनिवार को सत्ताधारी दल डीएमके के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा ने तमिलनाडु की डीएमके सरकार पर राज्य के अधिकार दूसरे राज्यों को देने का आरोप लगाया। साथ ही भाजपा ने परिसीमन विवाद को डीएमके का नाटक करार दिया। तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने इन विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया। इस प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं ने कर्नाटक के डिटी सीएम डीके शिवकुमार को भी काले झंडे दिखाए और नारेबाजी की।

अन्नामलाई का आरोप- पड़ोसी राज्यों के साथ मुद्दे पर नहीं बोलते सीएम

तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तमिलनाडु के पड़ोसी राज्यों के साथ कई मुद्दे लंबित हैं, लेकिन मुख्यमंत्री उन मुद्दों को नहीं उठाते। केरल के साथ मुल्लैपरियार बांध का मुद्दा है। कर्नाटक की सरकार कर्नाटक से होकर गुजरने वाली होसुर



‘प्रस्तावित परिसीमन को स्वीकार नहीं कर सकते’

जेएससी की बैठक के दौरान तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि ‘आज देश गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। भाजपा जनसंख्या नियंत्रण की सजा दे रही है। हम एक देश हैं और हम इसका सम्मान करते हैं, लेकिन हम इस प्रस्तावित परिसीमन को स्वीकार नहीं कर सकते। यह परिसीमन हमें राजनीतिक रूप से सीमित करेगा। यह बतौर अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों के तौर पर हमें दंडित करेगा। हम इस पक्षपाती परिसीमन को लागू करने से भाजपा को रोकना होगा।’

भारत में इनोवेशन की स्पीड उनकी अपेक्षा से बेहतर : बिल गेट्स

नई दिल्ली। माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक और अरबपति बिल गेट्स ने हाल ही में कहा कि भारत में इनोवेशन की स्पीड उनकी अपेक्षा से बेहतर है। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत के एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरने से न केवल देश को बल्कि पूरे विश्व को भी लाभ होगा। गेट्स ने गुरुवार को मुंबई में एक्सप्रेस अड्डा कार्यक्रम में इंडियन एक्सप्रेस समूह के एंजिवक्यूटिव डायरेक्टर अनंत गोयनका के साथ बातचीत में कहा, “आगर भारत 2047 प्लान के रास्ते पर बना रह सकता है तो यह सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद होगा।” उन्होंने आगे कहा, फ्लैट यह है कि आपके पास ह्यूमन फोर्स का 20 प्रतिशत हिस्सा है जो भागता है, लोकतांत्रिक चुनाव हैं और इसकी सभी प्राथमिकताएं तय होती हैं; स्वास्थ्य के लिए ज्यादा पैसा, शिक्षा के लिए ज्यादा पैसा- इस सबने एक बहुत अच्छी गतिशीलता बनाई है जहां आप अच्छे शासन में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

दक्षिण अफगानिस्तान में हथगोले हमले में 18 घायल

लश्कर गाह(वार्ता)। दक्षिणी अफानिस्तान के हेलमंद प्रांत में शुक्रवार को एक व्यक्ति के हथगोला फेंकने से 18 लोग घायल हो गए। प्रांतीय पुलिस कार्यालय की ओर से शनिवार को बताया कि यह घटना गेरेशक जिले के जाला बाजार क्षेत्र में शुक्रवार को उस समय घटी, जब दो भाई किसी मुद्दे पर झगड़ रहे थे और एक भाई के बेटे ने हथगोला फेंक दिया। इसमें 18 लोग घायल हो गए। इनमें से दो भाइयों की हालत गंभीर है।

मणिपुर में आठ उग्रवादी गिरफ्तार

इंफाल(वार्ता)। मणिपुर पुलिस और सुरक्षाकर्मियों ने पिछले 24 घंटों के दौरान विभिन्न अभियानों में आठ उग्रवादियों को गिरफ्तार किया। सुरक्षा बलों ने इम्फल पूर्वी जिले के एंड्रो थाना क्षेत्र के उंचोल माखा लेकाई से आरपीएफपीएल के एक सक्रिय कैडर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, वह आम जनता से जबरन वसूली की गतिविधियों में शामिल था। एक अन्य अभियान में, सुरक्षा बलों ने इम्फल पूर्वी जिले के पोरामपट थाना क्षेत्र के पास खुर्दू चिंगबम लेकाई स्थित कम्युनिटी हॉल के पास से पीआईडीपीके के एक सक्रिय कैडर को गिरफ्तार किया। वह भी आम जनता से जबरन वसूली की गतिविधियों में शामिल था। एक अलग घटना में, मणिपुर पुलिस ने इम्फल पश्चिम जिले में तीन सक्रिय कैडरों को उनके आवासों से गिरफ्तार किया। वे केंसीपी (अपुनबा) संगठन से जुड़े हुए थे। पुलिस ने उनके पास से एक 9 एमएम राइफल, एक मैगजीन जिसमें तीन राउंड थे, सयर नगर, डबल बैरल गन और अन्य सामान बरामद किए। मणिपुर पुलिस ने अभियान जारी रखते हुए तीनों व्यक्तियों के कमांडर को खुर्दू, इंफल स्थित उसके आवास से गिरफ्तार किया। मणिपुर पुलिस और एआर की संयुक्त टीम ने केंसीपी-पीडब्ल्यूजी संगठन के एक सक्रिय कैडर को मयांग लागजिंग बाजार, इंफल पश्चिम से गिरफ्तार किया। वह पैसे की मांग, धमकी देकर और इंफल क्षेत्र में और उसके आसपास स्थित विभिन्न स्टोन क्रशर, दुकानों और आम जनता से जबरन वसूली की गतिविधियों में शामिल था। सुरक्षा बलों ने बिष्णुपुर जिले के मोइरांग- थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोइरांग लमखाई, चुराचांदपुर पार्किंग से पीआईडीपीके (प्रो) के एक सक्रिय कैडर को गिरफ्तार किया।

तरनतारन सीमा पर ड्रोन बरामद जालंधर(वार्ता)। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और पंजाब पुलिस ने संयुक्त रूप से पंजाब की तरनतारन सीमा पर एक ड्रोन बरामद किया है। बीएसएफ के जनसंपर्क अधिकारी ने शनिवार को कहा कि नार्को ड्रोन के खिलाफ अभियान के दौरान आज पूर्वाह्न करीब 10:35 बजे तरनतारन जिले के गांव-डल से सटे एक खेत से एक डीजेआई मैविक 3 क्लासिक ड्रोन बरामद किया गया।

संसद में सरकार ने बताया-चीनी जमावड़े पर हमारी नजर है ‘भारतीय क्षेत्र पर चीन के अवैध कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया’ : पीएम मोदी

नई दिल्ली। चीन की आक्रामकता कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर भारतीय जमीन पर चीन की नापाक नजर का मामला सामने आया है। सरकार ने संसद को बताया कि भारत को चीन की ओर से दो नए क्षेत्र बसाने की जानकारी है। यहां चीनी जमावड़े पर भी हमारी नजर है। इन इलाकों के कुछ हिस्से लद्दाख में आते हैं, और सरकार ने राजनयिक माध्यमों से इस पर गंभीर विरोध दर्ज कराया है।

विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने शुक्रवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, ‘भारत सरकार ने भारतीय क्षेत्र पर चीन के अवैध कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया है। नए काउंटी बनाने से न तो इस क्षेत्र पर हमारी संप्रभुता के बारे में भारत की दीर्घकालिक और सुसंगत स्थिति पर कोई असर पड़ेगा, न ही चीन के अवैध और जबरन कब्जे को वैधता मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने इन घटनाक्रमों पर राजनयिक माध्यमों से अपना गंभीर विरोध दर्ज कराया है।

मंत्रालय से पूछा गया कि क्या सरकार को लद्दाख में भारतीय क्षेत्र को शामिल करते हुए होटन प्रान्त में दो नए



काउंटी स्थापित करने की जानकारी है, यदि हां, तो इस मुद्दे को हल करने के लिए सरकार द्वारा किए गए रणनीतिक और कूटनीतिक उपाय क्या हैं? प्रश्न में भारत द्वारा इन काउंटियों के निर्माण के खिलाफ दर्ज किए गए विरोधों का विवरण भी मांगा गया। साथ ही चीनी सरकार से प्राप्त जवाबों, यदि कोई हो, के बारे में भी पूछा गया। यह भी पूछा गया कि क्या सरकार ने अक्सई चिन क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रशासनिक और बुनियादी ढांचे के विकास का मुकाबला करने के लिए कोई दीर्घकालिक रणनीति तैयार की है।



सरकार ने क्या जवाब दिया?

उन्होंने कहा, ‘भारत सरकार चीन के होटन प्रान्त में तथाकथित दो नए काउंटियों की स्थापना से संबंधित चीनी पक्ष की घोषणा से अवागत है। इन तथाकथित काउंटियों के अधिकार क्षेत्र के कुछ हिस्से भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आते हैं। सरकार यह भी जानती है कि चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास कर रहा है।’ राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार सीमावर्ती

सीमा बुनियादी ढांचे के लिए बजट आवंटन में वृद्धि

सरकार की ओर से बताया गया कि पिछले दशक (2014-2024) में सीमा बुनियादी ढांचे के लिए बजट आवंटन में वृद्धि हुई है। मंत्री ने कहा कि अकेले सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने पिछले दशक की तुलना में तीन गुना अधिक खर्च किया है। उन्होंने कहा, ‘सड़क नेटवर्क, पुलों और सुरगों की संख्या की लंबाई में पहले की तुलना में काफी वृद्धि देखी गई है। इससे स्थानीय आबादी को कनेक्टिविटी प्रदान करने और हमारे सशस्त्र बलों के लिए बेहतर रसद सहायता प्रदान करने में मदद मिली है।’

क्षेत्रों के विकास के लिए बुनियादी ढांचे के सुधार पर सावधानीपूर्वक और विशेष ध्यान देती है, ताकि इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाया जा सके। साथ ही भारत की रणनीतिक और सुरक्षा आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सके।

‘न्यायिक जवाबदेही के मुद्दे का समाधान हो गया होता’: धनखड़

नई दिल्ली। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का नाम लिए बिना राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि अगर संसद में सर्वसम्मति से पारित किए गए तंत्र को अनुमति दी गई होती तो न्यायिक जवाबदेही के मुद्दे का समाधान हो गया होता। 2014 में संसद से पारित एनजेएससी को 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने असाविधानिक करार दिया था।

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले से बड़ी मात्रा में नकदी मिलने का मुद्दा कांग्रेस सांसद जयश्याम रमेश ने उठाया। इस पर सभापति ने कहा कि जिस तंत्र को इस सदन ने सर्वसम्मति से पारित किया था, बिना किसी मतभेद के, सरकार की पहल के समर्थन में थे। मैं उस ऐतिहासिक कानून की मौजूदा स्थिति जानना चाहता हूं। इसे भारतीय संसद ने पास किया था, इसे देश के 16 राज्य विधानसभाओं का समर्थन मिला था और इस पर संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत माननीय राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे, लेकिन उसे खत्म कर दिया गया। उन्होंने कहा कि उस ऐतिहासिक कानून को इस संसद से अभूतपूर्व समर्थन मिला। उसने इस समस्या को बहुत गंभीरता से लिया था। यदि उस समस्या का समाधान पहले कर



लिया गया होता तो शायद हमें इस प्रकार के मुद्दों का सामना नहीं करना पड़ता। सभापति ने कहा कि मुझे इस बात की चिंता है कि यह घटना घटित हुई और तुरंत सामने नहीं आई। यदि यह किसी राजनेता के साथ होता है तो वह तुरंत निशाने पर आ जाता है, जबकि किसी नौकरशाह या उद्योगपति के मामले में तत्काल प्रतिक्रिया दी जाती है। इसलिए, एक ऐसी प्रणाली आवश्यक है जो पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी हो। सभापति ने कहा कि मैं सदन के नेता, विपक्ष के नेता से संपर्क करूंगा और इस मसले पर सुव्यवस्थित चर्चा के लिए मार्ग खोजूंगा। सदन के नेता सत्तारूढ़ दल के अध्यक्ष भी हैं और विपक्ष के नेता मुख्य विपक्षी दल के अध्यक्ष भी हैं। मुझे विश्वास है कि उनकी और अन्य सदस्यों की सलाह उपयोगी होगी।

अमेरिकी सेना ने यमन के सादा प्रांत पर हवाई हमले किए

सना(वार्ता)। अमेरिकी सेना ने शुक्रवार शाम को यमन के उत्तरी सादा प्रांत पर हवाई हमले किए। हूमी द्वारा संचालित अल-मसीरा टीवी ने यह जानकारी दी। रिपोर्टों में कहा गया है कि हमलों ने प्रांत के पश्चिम में सकायन जिले को निशाना बनाया लेकिन कोई और विवरण नहीं दिया।

टेक्सटाइल में बांग्लादेश दुनिया भर में छाया, भारत क्यों नहीं बढ़ सका आगे? : सीएम योगी

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में शनिवार को पीएम मित्र पार्क इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, कैबिनेट मंत्री राकेश सचान समेत कई व्यापारियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में उद्यमियों और मंत्री ने अपनी-अपनी बातें रखीं। यूपी में इन्वेस्ट करने पर चर्चा की गई। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत को टेक्सटाइल हब के रूप में स्थापित करने का मिशन बनाया है। सीएम रहने उन्होंने गुजरात को टेक्सटाइल हब बनाया। अब इस विजन को देश में सात पाक स्थापित करके बढ़ाया। यूपी देश का एकमात्र राज्य है जहां पाक राजधानी में स्थित है।

निवेश मित्र के माध्यम से 500 से ज्यादा क्लनीयॉरेंस दिए आसपास के राज्यों की आबादी भी यूपी पर निर्भर है। तीन बेसिक जरूरतों में वस्त्र भी है।



यहां एक ही स्थान पर डिजाइन, सिलाई और कटाई का काम होता है। प्रदेश में आठ वर्ष में सकादात्मक माहौल तैयार किया। 33 सेक्टरल पॉलिसी वाला यूपी देश का पहला राज्य है। निवेश मित्र के माध्यम से 500 से ज्यादा क्लनीयॉरेंस दिए गए। रूह की मॉनिटरिंग के लिए निवेश सारथी है। मैं खुद मॉनिटरिंग करता हूं कि रूह के बाद क्या समस्या आ रही है? उसे दूर करने पर मंथन करता हूं। सीएम ने कहा कि इंडो-विक्ट्रितरण प्रक्रिया डीबीटी के माध्यम से करते हैं। निवेशक को मंच पर बुलाकर सम्मानित करते हैं। ताकि,

ये पता चले हम धरातल पर काम कर रहे हैं। जो कहा वो करके दिखाया। यूपी टेक्सटाइल के बेहतरीन हब के रूप में स्थापित हो सकता है। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है।

अयोध्या के पास अम्बेडकर नगर वस्त्र का गढ़ बना प्राचीन नगरी काशी और अयोध्या केवल आध्यात्मिक चिंतन का आधार नहीं थी। बल्कि, समृद्धि को भी नई ऊंचाई दी। वहां टेक्सटाइल की संभावनाएं अनंत तक से थी। वाराणसी में साड़ी, सिल्क क्लस्टर, कार्पेट के लिए वाराणसी, भदोही और मिर्जापुर का नाम आता है। अयोध्या के पास अम्बेडकर नगर वस्त्र का गढ़ बना। गोरखपुर के पास संत कबीरनगर, आजमगढ़, मऊ, लखनऊ में टेक्सटाइल का गढ़ है। पश्चिम में मेरठ और पिलखुआ भी हैं।

समीक्षा बैठक

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने नागपुर पुलिस मुख्यालय में की कानून-व्यवस्था की समीक्षा

दंगाइयों से वसूली जाएगी क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संपत्ति की कीमत : सीएम फडणवीस

मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने शनिवार को शहर में कानून व्यवस्था के संबंध में नागपुर पुलिस मुख्यालय में समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि नागपुर में क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संपत्ति की कीमत दंगाइयों से वसूली जाएगी और भुगतान न करने पर उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। फडणवीस ने कहा कि नागपुर का दौरा करने वाला कांग्रेस कमेटी का एक सदस्य अकोला हिंसा में आरोपी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने यह भी

कहा कि नागपुर हिंसा को खुफिया स्तर पर विफलता कहना गलत है, इसमें कोई राजनीतिक पहलू नहीं है। सीएम ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नागपुर यात्रा पर इस हिंसा का कोई असर नहीं पड़ेगा।

‘महिला पुलिस कांस्टेबलों से छेड़छाड़ की खबरें झूठी’

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा, “महिला पुलिस कांस्टेबलों पर पथर फेंके गए और छेड़छाड़ की खबरें झूठी हैं। नागपुर हिंसा में विदेशी



या बांग्लादेशी पहलू है या नहीं, इस संबंध में कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगा, जांच जारी है।” फडणवीस ने कहा कि पुलिसकर्मियों पर हमले बर्दाश्त

नहीं किए जाएंगे, सख्त कार्रवाई की जाएगी। फडणवीस ने कहा कि मध्य नागपुर के इलाकों में सोमवार को हुई हिंसा के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का

निर्धारित दौरा प्रभावित नहीं होगा। सीएम फडणवीस ने कहा, “‘पुलिसकर्मियों पर हमला करने वाले दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरी सरकार तब तक चैन से नहीं बैठेगी, जब तक पुलिस पर हमला करने वाले तत्वों का पता नहीं चल जाता और उनसे सख्ती से निपटा नहीं जाता।”

सीएम ने कहा कि दंगों में विदेशी या बांग्लादेशी हाथ होने के बारे में टिप्पणी करना अभी जल्दबाजी होगा, क्योंकि जांच जारी है। उन्होंने कहा कि हिंसा

हिंसा के दौरान क्षतिग्रस्त हुई संपत्तियों की कीमत दंगाइयों से वसूली जाएगी : फडणवीस नागपुर हिंसा पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने शनिवार को कहा कि हिंसा के दौरान क्षतिग्रस्त हुई संपत्तियों की कीमत दंगाइयों से वसूली जाएगी और भुगतान नहीं करने पर उनकी संपत्तियों को जब्त कर बेचा जाएगा। फडणवीस ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का विश्लेषण करने के बाद अब तक 104 दंगाइयों की पहचान की गई है और कानून के अनुसार 12 नाबालिगों सहित 92 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

का कोई राजनीतिक पहलू नहीं है। फडणवीस ने कहा कि इस घटना को ‘खुफिया विफलता’

नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसे बेहतर तरह से किया जा सकता था।

3 माह में बदलेगी कांग्रेस, जीतू पटवारी ने दिए संकेत !

कैलाश विजयवर्गीय को कहा-पाकिस्तान जाने से भ्रष्टाचार रुकता है तो मैं टिकट करा दूंगा

भोपाल/नवप्रदेश। प्रदेश कांग्रेस में अगले दो से तीन महीने में संगठन स्तर पर भारी बदलाव हो सकता है। इसके संकेत पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस द्वारा पंचायत कांग्रेस कमेटी और मोहल्ल कांग्रेस कमेटी का गठन किया जाएगा। जिला अध्यक्ष और ब्लाक अध्यक्षों की नियुक्ति की एक्सरसाइज कर ली गई है और जल्दी ही बदलाव का असर दिखाई देगा। उन्होंने पाकिस्तान जाने को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर कहा कि अगर पाकिस्तान जाने से भ्रष्टाचार रुकता है तो जाएँ, मैं टिकट करा देता हूं। शनिवार को मीडिया से चर्चा में पटवारी ने कहा कि संगठनात्मक मजबूती के लिए पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने एमपी और गुजरात को पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना है। इसकी खुशी है। हमारी एक्सरसाइज कम्पलीट हो गई है। पंचायत कांग्रेस कमेटी और शहरी क्षेत्र में मोहल्ल कांग्रेस कमेटी बनेगी। एक विधानसभा के प्रोग्राम का एक इंचार्ज होगा। जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की भी एक्सरसाइज हो गई है। उन्होंने कहा कि दो से तीन माह में पार्टी का एक नया चेहरा



मध्यप्रदेश में दिखेगा। महिला कांग्रेस कमेटी, 45 साल के ब्लॉक अध्यक्ष की बात हो, जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष की हैसियत जनप्रतिनिधि और विधायकों से ऊपर हो। ऐसा प्रयास किया जाएगा।

कोई मुद्दा नहीं मिलता तो पाकिस्तान का सहारा लेते हैं

मीडिया से चर्चा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पटवारी ने कहा कि, नफरत की बात करो, घृणा की बात करो, पाकिस्तान की बात करो, ऐसा प्रचलन सा चल गया है।

जब कोई मुद्दा नहीं मिलता तो पाकिस्तान का सहारा ले लेते हैं। सिर्फ सत्ता पाने के लिए, इस तरह के बयानों का सहारा लेते हैं। पटवारी ने इस मामले में नगरीय विकास मंत्री के पाकिस्तान संबंधी बयान को लेकर कहा कि, 25 साल से एमपी के नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय जो स्वीकार कर चुके हैं उनके विभाग में सबसे अधिक भ्रष्टाचार है। पाकिस्तान जाने से अगर भ्रष्टाचार रुकता है तो मैं उनकी टिकट करा दूंगा।

पटवारी ने कहा कि बीजेपी विधायकों के क्षेत्र के सरपंच बताते हैं कि उनके यहां

काम कराने के लिए दी जाने वाली राशि के बदले 30 प्रतिशत मांगे जाते हैं। पटवारी ने कहा कि इसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। जिसमें उन्हें याद दिलाया है कि शपथ लेने के समय उन्होंने विकास के लिए समान व्यवहार रखने की बात कही है। बीजेपी के विधायकों को विकास के लिए 15 करोड़ रुपए दे रहे हैं तो बाकी प्रदेश की जनता ने क्या गलत किया है जो उन्होंने विपक्ष के विधायक को चुन लिया है। सौरभ शर्मा का जिक्र करते हुए कहा कि, 52 किलो सोना मिला, डायरी मिली, मंत्री ने स्वीकार किया लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है।

प्रदेश कांग्रेस महामंत्री संगठन प्रभारी डॉ. संजय कामले ने बताया कि मप्र कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी 26 मार्च से प्रदेश के सघन दौरे पर रहेंगे। चौधरी 26 मार्च को सतना पहुंचेंगे और वहां से रीवा, मैहर, मऊगंज, सिंगरौली सहित अन्य जिलों के प्रवास पर रहकर इन जिलों के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठक लेंगे, साथ ही आगामी रणनीति पर विस्तृत चर्चा करेंगे।

एमपी में बढ़ते महिला अपराधों को लेकर महिला कांग्रेस का प्रदर्शन,अध्यक्ष बोलीं-सुरक्षा देने में सरकार फेल

भोपाल/नवप्रदेश। प्रदेश में महिला अपराधों को लेकर सियासत गरमा गई है। विधानसभा में हंगामे के बाद कांग्रेस सड़क पर उतरी है। शनिवार को महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। बेटी बचाओ पखवाड़ा की भी शुरुआत कांग्रेस करेगी। मध्यप्रदेश में महिला अपराधों को लेकर सियासत गरमा गई है। विधानसभा में हंगामे के बाद महिला कांग्रेस सड़क पर उतरी है। शनिवार को महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान महिला कांग्रेस ने कहा महिलाओं पर अपराध और अत्याचार कम नहीं हो रहे हैं। सिलसिलेवार रूप से अभियान और आंदोलन चलाए जाएंगे। प्रदेश के हर जिला मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन होगा। इसी कड़ी में बेटी बचाओ पखवाड़ा की भी शुरुआत कांग्रेस करेगी। प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष विभा पटेल बताया कि प्रदेश के सतना जिले में ढाई साल की मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी, सहित प्रदेश भर में महिलाओं, युवतियों, नाबालिगों के साथ प्रदेश में लगातार हो रही की घटनाओं पर कड़ी आपत्ति जताते हुए आज महिला कांग्रेस नेत्रियों द्वारा महिलाओं-बच्चियों की सुरक्षा में नाकाम प्रदेश की नाकारा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर महिला उत्पीड़न को लेकर विरोध दर्ज किया गया।

प्रदेश नें रोज बलात्कार की 20 घटनाएं

विभा पटेल ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं, युवतियों और अबोध-मासूम बच्चियों के साथ शोषण, दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। प्रदेश में दिल दहलाने वाली रोज बलात्कार की लगभग 20



अमानवीय घटनाएं सामने आ रही है, जो इंसानियत को शर्मसार कर रही हैं। प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था के चलते आपराधिक सोच के व्यक्तियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे बेखौफ और निडर होकर घटनाओं को अंजाम देने से नहीं चूक रहे हैं। पटेल ने कहा कि सतना में घटित हुई घटना से साबित होता है कि प्रशासन बहन-बेटियों को सुरक्षा देने में पूरी तरह नाकाम है। प्रदेश में महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। बढ़ते महिला अपराधों से सभ्य समाज कलंकित हो रहा है। इन घटनाओं से महिलाओं, बच्चियों में भय और आमजन में आक्रोश व्याप्त है। पटेल ने कहा कि प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जो स्वयं गृहमंत्री का दायित्व संभाल रहे हैं, उनसे न तो मुखिया की कुर्सी संभल रही है और न ही गृहमंत्री का दायित्व ठीक से संभाल पा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि गृहमंत्री का दायित्व किसी अच्छे, योग्य और जिम्मेदार व्यक्ति को सौंप दें, ताकि प्रदेश की कानून-व्यवस्था को चौक-चौबंद किया जा सके, अपराधियों पर लगाम लगे, ताकि प्रदेश में महिलाओं, बच्चियों को सुरक्षा और सम्मान मिल सके, आमजन को आपराधिक प्रवृत्ति के असामाजिक तत्वों से राहत

भोपाल में छठी बटालियन के जवान ने फांसी लगाई कर्ज से परेशान था, डिलीवरी कराने पत्नी गई है मायके

भोपाल/नवप्रदेश। भोपाल की नेहरू नगर पुलिस लाइन में रहने वाले छठी बटालियन के जवान भूर सिंह जामोद ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। वह कर्ज से परेशान थे। पुलिस को उनके घर से लोन संबंधी दस्तावेज मिले हैं। हालांकि उनके पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। उनकी पत्नी प्रेमेन्ट है। डिलीवरी के लिए जवान ने कुछ दिन पहले पत्नी को मायके भेज दिया था। मामले में कमला नगर पुलिस ने मार्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। घटना शुक्रवार रात की है। पीएम के बाद शनिवार दोपहर शव परीजनों को सौंप दिया गया है। भूर सिंह जामोद (35) पुत्र जाम सिंह जामोद मूल रूप से देही जिला धार के रहने वाले थे। छठी बटालियन भोपाल में पदस्थ थे और नेहरू नगर पुलिस लाइन में रहते थे। फिलहाल अटैचमेंट पर उनकी ड्यूटी सीएम हाउस में चल रही थी। मामले की जांच कर रहे एसआई शैलेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि उनके घर से लोन संबंधी दस्तावेज बरामद किए हैं। परीजनों और परिचितों ने भी प्रारंभिक तौर पर कर्ज के चलते तनाव की बात बताई है। उनके पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। जिससे आत्महत्या के सही कारणों का खुलासा नहीं हो सका है।

सात साल पहले हुई थी शादी

भूर सिंह की शादी सात साल पहले हुई थी। उनका एक 6 वर्ष का बेटा है। जबकि दूसरे बच्चे का जन्म होने वाला है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि पति-पत्नी के बीच किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं था। भूर सिंह का मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है। जिसकी जांच कराई जाएगी।

भोपाल में छेड़छाड़ करने वाले को एक साल की सजा

7 साल बाद आया फैसला; एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया

भोपाल/नवप्रदेश। भोपाल में छेड़छाड़ करने वाले को न्यायिक मजिस्ट्रेट शोभना गौतम ने एक साल की सजा और एक हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शनिवार को यह फैसला सुनाया गया है। घटना 4 अप्रैल 2017 की है। सात साल के ट्रायल के बाद यह फैसला सुनाया गया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि 3 अप्रैल 2017 को लगभग 9:30 बजे आरोपी राकेश अहिरवार उसे न्यू शंकर नगर छोला में रुकाई। उसने कहा कि, वो उसे पंसद करता है, फिर बैड टच करने लगा। जब पीड़िता ने चिल्लाया, तो उसकी बड़ी बहन मौके पर पहुंची लेकिन तब तक आरोपी वहां से भाग गया। वहीं जाते हुए आरोपी ने पीड़िता को धमकी देते हुए कहा कि, अगर उसने इसकी शिकायत की तो वो उसे जान से मार देगा।

इसके बाद पीड़िता ने पुलिस थाना छोला मॉडर में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अपराध क्रमांक 165/2017 धारा 341, 354, 506 के तहत मामला दर्ज किया गया और केस की जांच शुरू की गई। जिसके बाद आरोपी राकेश अहिरवार को दोषी ठहराते हुए उसे 1 साल की सजा के साथ 1000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया।

भ्रष्टाचार के आरोप में फरार टीआई को अग्रिम जमानत

वकील के तर्क- आरोपी एसएसआई से कोई लेना-देना नहीं

कार्रवाई कराई थी इस लिए फंसा दिया

भोपाल/नवप्रदेश। भोपाल में फर्जी कॉल सेंटर संचालकों को बचाने के एवज में रिश्तत मांगने के आरोप में अंडर ग्राउंड हुए टीआई जितेंद्र गड़वाल को जबलपुर हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। उनकी जमानत को मंजूर कर लिया गया है। हाईकोर्ट जज मनिंदर एस भट्टाई की कोर्ट ने उनको अग्रिम जमानत का लाभ दिया है। इधर केस के मुख्य आरोपी एएसआई पवन रघुवंशी अब भी फरार हैं। उसके साथ एएसआई मनोज सिंह और प्रधान आरक्षक धर्मेन्द्र सिंह सहित अन्य आरोपी मोहन अंशुल पार्षद भी फरार हैं।

बता दें कि पवन पर रिश्तत के 4.94 लाख रुपए घर में रखने के आरोप हैं। वह लाइन हाजिर होने के बाद भी अहम केसों की डायरियां अपने साथ ले गया था। उसका आचरण लगातार संदिग्ध था। कार्यवाहक निरीक्षक जितेंद्र गड़वाल ने डीसीपी जोन-1 को गोपनीय पत्र के माध्यम से उसके संदिग्ध आचरण की जानकारी दी थी। इस आधार पर 28 फरवरी को उसे लाइन हाजिर किया गया। इसकी रिपोर्ट रोजनामचा में भी दर्ज की गई थी। उनके वकील की ओर से यह तमाम तर्क कोर्ट में दिए।



जिसके आधार पर उन्हें जमानत का लाभ मिला।

तत्काल डायरियां सौंपने का आदेश दिया था

टीआई ने पवन को लाइन हाजिर किए जाने के बाद तत्काल प्रभाव से उसे अपने पास मौजूद तमाम केस डायरियों का चार्ज दूसरे को ट्रांसफर करने के आदेश दिए गए, लेकिन वह डायरियां अपने साथ लेकर चला गया। इन डायरियों में फर्जी कॉल सेंटर केस की डायरी भी मौजूद थी। इस बात की

रिपोर्ट भी रोजनामचा में दर्ज है।

सुबह तक जिस थाने में टीआई थे, शाम को वहीं केस दर्ज

रिश्तत के इस मामले में टीआई जितेंद्र गड़वाल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज है। खास बात यह है कि जिस ऐशबाग थाने में जितेंद्र गड़वाल 5 मार्च सुबह 11 बजे तक तबौर टीआई पदस्थ थे, उसी थाने में उन पर एफआईआर दर्ज हुई। उनके साथ पवन रघुवंशी, प्रधान आरक्षक धर्मेन्द्र और टीकमगढ़ से

रिश्तत देने वाले अंशुल उर्फ मोना जैन को आरोपी बनाया गया है।

उगी के कॉल सेंटर के इसी मामले में कार्रवाई में लापरवाही को लेकर पुलिस ने ऐशबाग थाना टीआई जितेंद्र गड़वाल सहित चार पुलिसकर्मियों को सरपेंड किया था। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा ने बताया कि चारों आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है।

यह है पूरा मामला

भोपाल में प्रभात चौराहा स्थित एक बिल्डिंग में संचालित 'आइडियालॉजी एडवांस स्टॉक प्राइवेट लिमिटेड' नामक कॉल सेंटर पर पुलिस ने 23 फरवरी में लापरवाही को छपा मार कार्रवाई की थी। शुक्रवार को पुलिस ने कॉल सेंटर को पूरी तरह से सील कर दिया था।

एएसआई पवन रघुवंशी के अनुसार, कॉल सेंटर में कार्यरत युवक-युवतियों ने पूछताछ में खुलासा किया कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर बाजार में निवेश से संबंधित विज्ञापन प्रसारित करते थे+।

पुलिस ने सेंटर से 80 से अधिक कंप्यूटर और 26 मोबाइल सिम जब्त की गई थी। पुलिस को पवन पर्व की बहुत-बहुत बधाई और सरगना की एक डायरी भी मिली थी, जिसमें 100 से अधिक नाम और मोबाइल नंबर दर्ज थे। इन सभी लोगों को थाने बुलाकर पूछताछ हुई थी।

त्यौहार का सामाजिक एकजुटता में महत्वपूर्ण योगदान : राज्यमंत्री गौर राज्यमंत्री पटेल मार्केट व्यापारी संघ के होली मिलन समारोह में हुई शामिल



भोपाल/नवप्रदेश। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने कहा कि त्योहार का सामाजिक एकजुटता में महत्वपूर्ण योगदान है। पर्व, त्योहार के आयोजन से हमारी संस्कृति समृद्ध हो रही है। ये सामाजिक एकता को भी मजबूत कर रहे हैं। राज्यमंत्री श्रीमती गौर शनिवार को भानपुर भोपाल में पटेल मार्केट व्यापारी संघ द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह को संबोधित कर रही थी।

राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने कहा कि सनातनी परंपरा अनुसार त्यौहार समाज को एकजुट रखने का काम कर रहे हैं। त्यौहारों का उल्लस, उत्साह हमारे मन और जीवन को आनंद से भर देता है। हमारे त्यौहार जीवन में तनाव को दूर कर आनंद की अनुभूति कराते हैं।

राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने कहा कि समारोह के माध्यम से सनातन संस्कृति का सम्मान करने के लिए यहां उपस्थित सभी व्यापारी बंधुओं को होली और रंग पंचमी के पावन पर्व की बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। होली मिलन समारोह में स्थानीय पार्षद श्री विकास पटेल, श्री राजू राठौर, श्री नीलेश गौर, श्री प्रकाश पटेल, श्री विनोद साहू, श्री प्रमोद गुप्ता, श्री मुकेश यादव सहित व्यापारी बंधु मौजूद रहे।

भोपाल के एमपी नगर में पकड़ाया 15 किलो गांजा: उड़ीसा से लाकर भोपाल में बेचने की फिराक में थे 4 तस्कर

भोपाल/नवप्रदेश। भोपाल क्राइम ब्रांच टीम ने उड़ीसा से भोपाल गांजा तस्करी करने वाले 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 15 किलो 160 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया। जिसकी कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही है। क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि एमपी नगर जोन-1 स्थित यश बैंक के सामने 4 लोग थैलों में गांजा रखकर ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं। सूचना पाकर क्राइम ब्रांच थाना प्रभारी अशोक मरावी और उनकी टीम मौके पर पहुंची। यहां घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

पेड़ के पास बैठे थे 4 संदिग्ध लोग

क्राइम ब्रांच को एक विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि एमपी नगर जोन-1 में स्थित यश बैंक के सामने एक पेड़ के पास 4



संदिग्ध लोग बैठे हैं। ये चारों लोग अपने पास थैले लिए हुए हैं, जिनमें गांजा भरा हुआ है। वे किसी ग्राहक को बेचने के लिए इंतजार कर रहे हैं। सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच थाना प्रभारी अशोक मरावी ने तुरंत अपनी टीम को सक्रिय

किया। वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराने के बाद एक विशेष टीम का गठन किया गया। जिसमें उप निरीक्षक इरशाद अंसारी, अजीज खान, सहायक उप निरीक्षक चंद्रमोहन मिश्रा, सहायक उप निरीक्षक रामकुमार गौतम, प्रधान

आरक्षक विश्वजीत भार्गव, मजफ्फर अली, आरक्षक वृजमोहन ब्यास, मुकेश शर्मा, शादीब, महावीर, ऋषिकेश त्यागी, विवेक नामदेव और संध्या शर्मा को शामिल किया गया।

पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर योजना बनाकर कार्रवाई की। सभी पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में थे ताकि तस्करों को किसी प्रकार का संदेह न हो। जब टीम यश बैंक के सामने पहुंची, तो वहां चार व्यक्ति अपने-अपने थैले लिए बैठे थे। पुलिस ने धीरे-धीरे इलाके की घेराबंदी की ताकि कोई भी आरोपी भाग न सके। जैसे ही पुलिस ने चारों को पकड़ा और उनकी तलाशी ली, तो उनके थैलों में पत्ती में लिपटा हुआ गांजा मिला। पूछताछ करने पर आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे उड़ीसा से यह गांजा लेकर आए थे और भोपाल में इसे बेचने की फिराक में थे।

इनको किया गिरफ्तार
अर्जुन कुचबंदिया (19) : निवासी हरदा, मजदूर
सूरज कुचबंदिया (35) : निवासी रायसेन, हलवाई
लक्ष्मण कुचबंदिया (25) : निवासी हरदा, मजदूर
नर्मदा कहार उर्फ छोटे (27) : निवासी रायसेन, पुराने कपड़ों का व्यवसाय
आरोपियों की तलाशी में प्लास्टिक के थैलों में भरा 15 किलो 160 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में उन्होंने गांजा उड़ीसा से लाकर भोपाल में बेचने की बात स्वीकार की। क्राइम ब्रांच ने आरोपियों के खिलाफ धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत अदालत में पेश किया जाएगा।



साय ने किया खिलाड़ियों का सम्मान, कहा-आपने छत्तीसगढ़ का सिर गर्व से ऊंचा किया

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राष्ट्रीय खेल पदक विजेता खिलाड़ियों को बताया छत्तीसगढ़ का गौरव: छत्तीसगढ़ को दी ओलंपिक विजेता बनने की शुभकामनाएं

रायपुर/नवप्रदेश। आप सभी ने अपनी मेहनत, प्रतिभा और जुनून से छत्तीसगढ़ का नाम राष्ट्रीय पटल पर रोशन किया है। ये सिर्फ आपकी नहीं, पूरे प्रदेश की जीत है। आप प्रदेश के खेल जगत के हीरो हैं। सरकार आपको तराशेगी, निखारेगी और अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाएगी। आपके लिए हर संभव ससंधन और समर्थन उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज मुख्यमंत्री निवास में आयोजित राष्ट्रीय खेल विजेता सम्मान समारोह में गोवा और उत्तराखंड नेशनल गेम्स में पदक जीतने वाले छत्तीसगढ़ के

खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री ने समारोह में गोवा में वर्ष 2023 में सम्पन्न 37वें नेशनल गेम में छत्तीसगढ़ के पदक विजेता 72 खिलाड़ियों को और वर्ष 2025 में उत्तराखंड में सम्पन्न 38 वें नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ पदक विजेता 58 खिलाड़ियों को सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए कहा कि आप सभी छत्तीसगढ़ के गौरव हैं। आपने न सिर्फ पदक जीते हैं, बल्कि पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया है। आप सभी ने छत्तीसगढ़ का सर गर्व से ऊंचा किया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने खिलाड़ियों से आह्वान किया कि वे अब एशियाड, कॉमनवेल्थ और ओलंपिक जैसे वैश्विक मंचों पर छत्तीसगढ़ और भारत का नाम रोशन करें।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अपने संबोधन में कहा कि आज गोवा और उत्तराखंड में हुए नेशनल गेम्स



विजेता खिलाड़ियों का सम्मान कर हम सब बहुत गौरव का अनुभव कर रहे हैं। आप सभी ने अपने शानदार प्रदर्शन से छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है इसके लिए आप सभी की जितनी भी प्रशंसा की जाए, कम है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हम लोगों ने गोवा में पदक जीतने वाले राज्य के 72 खिलाड़ियों को 1 करोड़ 7 लाख 60 हजार रुपए की राशि एवं उत्तराखंड

में नेशनल गेम्स जीतने वाले 58 खिलाड़ियों को 87 लाख 60 हजार रुपए की राशि प्रदान कर सम्मानित किया है। इस प्रकार समारोह के माध्यम से छत्तीसगढ़ के 130 राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को कुल 1 करोड़ 95 लाख 20 हजार रुपए की सम्मान राशि हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के खाते में अंतरित की जा रही है।

ओलंपिक विजेता खिलाड़ियों

के लिए विशेष पुरस्कारों की हमारी सरकार ने की है घोषणा : मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश के जो भी खिलाड़ी ओलंपिक खेलों में पदक लाएंगे, उनके लिए विशेष पुरस्कारों की घोषणा हमारी सरकार ने की है। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को तीन करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को दो करोड़ रुपए तथा कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को एक करोड़ रुपए देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है।

खिलाड़ियों को बेहतरीन खेल अधोसंरचना उपलब्ध कराने सरकार कर रही प्रयास : मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ की खिलाड़ियों में काफी दमखम है। हम छत्तीसगढ़ में खेलों के लिए शानदार अधोसंरचना तैयार कर रहे हैं। खेलो इंडिया के 7 नये सेंटर हमने आरंभ किये हैं। छत्तीसगढ़ में हर तरह की खेल

बस्तर क्षेत्र में खेलों की वापसी, नई आशा और विश्वास का प्रतीक

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बरसों तक माओवादी आतंक झेलने के बाद जब बस्तर में अमन लौटा तो खेल भी लौटा, वहां हमने बस्तर ओलंपिक का आयोजन कराया। उन्होंने कहा कि जहां कभी पांव भी रखने से लोग डरते थे, आज वहीं हज़ारों खिलाड़ी खेल रहे हैं। लोगों में जबर्दस्त उत्साह दिखा, पूरे देश में कम ही हुआ होगा कि किसी खेल आयोजन में 1 लाख 65 हजार प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और वह भी ऐसा आयोजन जो बस्तर संभाग में हुआ जहां की आबादी शेष जगहों की तुलना में काफी विरल है। इसमें ऐसे लोगों ने भी हिस्सा लिया, जो नक्सल हिंसा में अपने अंग गंवा चुके थे। आत्मसमर्पित नक्सलियों ने भी हिस्सा लिया। नक्सल हिंसा प्रभावित परिवारों ने भी हिस्सा लिया। इस आयोजन से प्रदेश के खेलप्रेमियों की उम्मीदें काफी बढ़ी हैं।

प्रतिभाएं हैं। हमने इसे ध्यान में रखते हुए अलग-अलग तरह के खेलों के लिए कोचिंग की विशेष व्यवस्था की है। इसी साल हमने तीन नई अकादमी की शुरुआत की है। रायपुर में टेनिस, राजनांदगांव में हाकी और नारायणपुर में मल्लखंभ अकादमी हमने आरंभ की है। परंपरागत खेलों को मिलेगा नया जीवन: 20 करोड़ रुपए की

छत्तीसगढ़ क्रीडा प्रोत्साहन योजना : मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ अपने परंपरागत खेलों के लिए भी प्रसिद्ध है। इन खेलों का समुचित विकास होता रहे, इसके लिए हमने 20 करोड़ रुपए का प्रावधान छत्तीसगढ़ क्रीडा प्रोत्साहन योजना के तहत किया है। हमारी सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

संक्षिप्त खबरें

और सड़क पर बहने लगी 1.89 करोड़ की ‘अवैध शराब’

राजनांदगांव/नवप्रदेश। राजनांदगांव के सीआईटी कॉलेज बाईपास के पास सड़क में 1.89 करोड़ रुपए की अवैध शराब नष्ट की गई, ये नजारा वहां जिन्होंने भी देखा सबके मुंह में पानी आ गया और सभी ये सोचने लगे कि काश ये हमें मिल जाती। दरअसल कलेक्टर संजय अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग की उपस्थिति में 39,918.417 बल्क लीटर अवैध शराब को नष्ट किया गया। इस शराब की कुल कीमत 1,89,77,818 रुपये थी। कार्रवाई के दौरान 18 थाना/चौकी के 1187 मामलों में जन्ब की गई शराब शामिल थी

कोयला चोरी कर भाग रहे बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी को मारी टक्कर

बाल-बाल बचे पुलिसकर्मী, आरोपी गिरफ्तार

सूरजपुर/नवप्रदेश। जिले में कोयला चोर बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. विश्रामपुर पुलिस ने एसईसीएल में कोयला चोरी मामले में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से छेटा हाथी में लोड 70 बोरी कोयला बरामद किया गया है. जानकारी के मुताबिक, एसईसीएल में दो व्यक्त कोयला को गाड़ी में भरकर चोरी कर ले जा रहे थे. शुक्रवार देर रात पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस ने वाहन को रोकने का प्रयास किया. इस बीच वाहन चालक ने रोकने की बजाय पुलिस वाहन को टक्कर मारकर भागने की कोशिश की. हालांकि पुलिस टीम बाल-बाल बची और वाहन को रोकने में सफलता हासिल की. पुलिस ने छेटा हाथी में लोड 70 बोरी कोयला को जन्ब किया. साथ ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वहीं पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

तस्करी की आशंका: एक महीने पहले जलाशय में मिला भालू का शव

बालोद/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ के बालोद से आज एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है. बीते महीने बिना पोस्टमार्टम के दफनाया, फॉरेस्ट गार्ड और डिप्टी रेंजर को शो कॉज नोटिस जारी

को सूचित न करते हुए गोपनीय तरीके से मृत भालू के शव को दफना दिया. इस घटना का खुलासा होते ही वन विभाग में हड़कंप मच गया. मामले के खुलासे के बाद DFO के निर्देशानुसार बालोद वन विभाग और वेटनारी डॉक्टर तांदुला जलाशय के किनारे घटना स्थल पहुंचे और खुदाई कर भालू के शव को बाहर निकाले. वहीं बालोद छद्मह ने इस मामले में तत्काल फॉरेस्ट गार्ड और डिप्टी रेंजर को कारण बताओ नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है. साथ ही देर होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी है. इस मामले के उजागर होने के बाद वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के जानवरों के अंगों की तस्करी में शामिल होने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि भालू के शव के पोस्टमार्टम और जांच पूरी होने के बाद ही मामले की पूरी सच्चाई सामने आ सकेगी.

15,00,00,000 की ठगी का छत्तीसगढ़ पुलिस ने किया खुलासा फ्रिटोकरंसी में होता था लेन-देन

बिलासपुर/नवप्रदेश। ऑनलाइन ठगी को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का बिलासपुर पुलिस ने पर्दाफ़ाश किया है. ऑनलाइन जॉब और वेबसाइट में इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर ठगी को अंजाम देने वाले तीन शातिर आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने 15 करोड़ से अधिक की राशि का सट्टा और फ्रिटोकरंसी में लेन-देन भी किया है दरअसल, शहर के मोपका निवासी शिक्षक सौरभ साहू बीते दिनों साइबर फ्रैंड के शिकार हुए थे. ऑनलाइन जॉब और वेबसाइट में इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर ठगों ने शिक्षक से 48 लाख की ठगी की थी. रेंज साइबर पुलिस ने केस दंड कर मामले की जांच शुरू की. तकनीकी साक्ष्यों के साथ पुलिस को इसमें बड़े गिरोह के शामिल होने और आरोपियों के ठगण, महाराष्ट्र में होने की सूचना मिली. टीम ने थाणे में दंबिश देकर आरोपी शाकिब अंसारी, अंसारी मेराज और अंसारी पुंजेल को गिरफ्तार किया. जांच में पता चला कि तीनों आरोपी ऑनलाइन गेमिंग, ट्रेडिंग, वर्क फ्रम होम, रेंटिंग रिब्यू, बीमा पॉलिसी और डिजिटल असेस्ट के नाम पर अधिक लाभ दिलाते

शादी से लौट रहा परिवार हुआ हादसे का शिकार, 19 घायल

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ में शनिवार को अलग-अलग क्षेत्रों में रफ्तार का कहर देखने को मिला है. आज तीन अलग-अलग सड़क हादसे हुए हैं. ये दुर्घटनाएं बालोद और जीपीएम जिले में हुए हैं. इन हादसों में कुल 19 लोग घायल हुए हैं. सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है.

पहला हादसा बोलद में हुआ है, जहां शादी कार्यक्रम से वापस लौट रहे एक ही परिवार के 17 लोग सड़क हादसे का शिकार हो गए. हादसे में पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि अन्य लोगों को मामूली चोटें आई हैं. घायलों में दो बच्चे सहित महिलाएं शामिल हैं.

जानकारी के मुताबिक, बालोद थाना क्षेत्र अंतर्गत मड़वापथरा गांव के पास शादी से वापस लौट रहे परिवार की कार दुर्घटना का शिकार हो गई. उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई. सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

नाली में जा घुसा अनियंत्रित ट्रेलर : वेंकटनगर मुख्य सड़क मार्ग में एक और हादसा हुआ है. गिरवर



खड़ी स्कूल बस और ट्रक को ट्रेलर ने मारी टक्कर

गौरेला पेण्ड्रा मरवाही के वेंकटनगर मुख्य सड़क मार्ग में रफ्तार का कहर नहीं थम रहा है. गौरेला के मथुरा पेट्रोल पंप के पास खड़ी स्कूल बस और ट्रक को तेज रफ्तार ट्रेलर ने टक्कर मार दी. इस टक्कर में ट्रेलर का ड्राइवर हुआ चोटिल हो गया. घटना के बाद चालक को अस्पताल में भर्ती किया गया है. राहत की बात रही की टक्कर के बाद वोल्टेज से भरा ट्रक को नुकसान नहीं पहुंचा.

गांव में ट्रेलर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे नाली में जा घुसा. हादसे में एक ड्राइवर घायल हो गया, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. हादसे के बाद सड़क

में लगा लंबा जाम. मौके पर पुलिस पहुंचकर सड़क में लगे जाम को हटाने में जुटी गई. जिले में बढ़ते सड़क हादसे को लेकर लोगों में आक्रोश है.

छत्तीसगढ़ में अचानक गायब हुई गर्मी कहीं झमाझम बारिश, कहीं गिरे ओले

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ के साथ ही शुरुवार को राजधानी रायपुर में मौसम में बदलाव आया. पिछले कुछ दिनों से लग रही गर्मी अचानक से गायब हो गई, मॉदिरहसौद क्षेत्र में दोपहर लगभग 3 बजे शुरुवार रात का मौसम ऐसा था मानो ठंड फिर से लौट आई हो.

जिले के हरदोमा वन परिक्षेत्र में 24 फरवरी को तांदुला जलाशय के किनारे एक भालू का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था. इसकी जानकारी नियमानुसार छद्मह कार्यालय को दिया जाना था, लेकिन वनकर्मी और विभागीय अधिकारियों ने उच्च अधिकारियों को सूचित न करते हुए गोपनीय तरीके से मृत भालू के शव को दफना दिया. इस घटना का खुलासा होते ही वन विभाग में हड़कंप मच गया. मामले के खुलासे के बाद DFO के निर्देशानुसार बालोद वन विभाग और वेटनारी डॉक्टर तांदुला जलाशय के किनारे घटना स्थल पहुंचे और खुदाई कर भालू के शव को बाहर निकाले. वहीं बालोद छद्मह ने इस मामले में तत्काल फॉरेस्ट गार्ड और डिप्टी रेंजर को कारण बताओ नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है. साथ ही देर होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी है. इस मामले के उजागर होने के बाद वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के जानवरों के अंगों की तस्करी में शामिल होने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि भालू के शव के पोस्टमार्टम और जांच पूरी होने के बाद ही मामले की पूरी सच्चाई सामने आ सकेगी.

बजे तक आसमान में पूरी तरह बदली छ

वहीं माना, धनेली, अभनपुर, मॉदिरहसौद क्षेत्र में दोपहर लगभग 3 बजे के आसपास तेज बारिश शुरू हो गई. इस

दौरान शहर में कहीं हल्की बारिश हुई तो कहीं बूंदबांदा हुई. मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम विश्वोभ द्रोणिका के रूप में 5.8 किलोमीटर ऊंचाई पर 76 डिग्री पूर्व और 32

डिग्री उत्तर में स्थित है. एक हवा का फ्लाइट को डायवर्ट करने की नौबत आई. अंदरूनी कर्नाटक तक 1.5 किलोमीटर

ऊंचाई तक विस्तारित हैं. प्रदेश में 48 घंटों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट की संभावना है. राजधानी में 22 मार्च को आकाश आंशिक मेघमय रहने, गरज-चमक के साथ बौछारे पड़ने की संभावना है. अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रह सकेगी है.

रखते हुए कार्य कर रही है।

नीमच और मुरैना-वैश्विक स्तर के सौर

पार्क प्रदेश में बड़ी सौर परियोजनाएं आकार ले रही हैं, जिनमें नीमच 170 मेगावाट सौर परियोजनाऔर मुरैना हाथ्यब्रिड उत्पादन और स्टोरेज पार्क शामिल हैं।

नीमच सौर परियोजना में अब तक 100 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण किया जा चुका है और परियोजना क्रियाशील हो चुकी है। भारतीय रेलवे और मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी (एमपीपीएमसीएल) के लिए ये परियोजना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान में भारतीय रेल को ऊर्जा की आपूर्ति मध्यप्रदेश से ही की जा रही है।

मुरैना हाथ्यब्रिड उत्पादन और स्टोरेज पार्क में दिन में सौर ऊर्जा उत्पादन कर संग्रह किया जाएगा, जबकि रात में पीक-ऑवर में इस संग्रहित विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति की जाएगी। इस पार्क में उन्नत ऊर्जा प्रबंधन तकनीकों का उपयोग किया जाएगा।

किसानों के लिए ऊर्जा आत्मनिर्भरता मध्यप्रदेश सरकार किसानों को अतिरिक्त आय और ऊर्जा आत्मनिर्भरता देने के लिए

कुटुम्ब न्यायालय के न्यायाधीश पर दुर्व्यवहार का आरोप

अधिवक्ताओं ने की स्थानांतरण की मांग, न्यायालय के सभी कार्यों का किया बहिष्कार

मुंगेली/नवप्रदेश। कुटुम्ब न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ अधिवक्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है. न्यायाधीश के स्थानांतरण की मांग करते हुए जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी और सदस्यों ने प्रस्ताव भी पारित किया, जिसमें जिला न्यायालय के सभी कार्यों का बहिष्कार का निर्णय लिया गया. इसमें राजस्व न्यायालय भी शामिल है.

शिकायत में क्या है पड़िए

जिला अधिवक्ता संघ की ओर से जिला अध्यक्ष राजमन सिंह द्वारा जारी प्रेस विज्ञापि में कहा गया है कि मुंगेली जिला न्यायालय में जब से कुटुंब न्यायालय की स्थापना हुई है. तब से कुटुंब न्यायालय के पीठासीन महिला न्यायाधीश द्वारा अधिवक्ता संघ मुंगेली अधिवक्तागण के साथ व्यवहार अच्छ नहीं रहा, लेकिन संघ के सदस्य पक्षकारों के हित को ध्यान में रखते उक्त न्यायालय में कार्य करते रहे. आज से लगभग 2

माह पूर्व जब कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश का व्यवहार अधिवक्ता संघ मुंगेली के सदस्यों के साथ असह्य हो गया, तब अधिवक्ता संघ मुंगेली द्वारा प्रस्ताव पास कर कुटुंब न्यायालय का लगभग 1 माह तक बहिष्कार किया गया. इसकी सूचना जिला न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के रजिस्टार जनरल एवं पोर्ट फेलिया जज छोगो उच्च न्यायालय (मुंगेली) को भी दी गई, उच्च न्यायालय के रजिस्टार जनरल द्वारा जिला न्यायाधीश मुंगेली को निर्देशित किया गया कि उभयपक्ष के मध्य बातचीत के माध्यम से सामंजस्य स्थापित कर समस्या का समाधान कराये.

समझौते में क्या हुआ ?

जिला न्यायाधीश मुंगेली द्वारा अधिवक्ता संघ मुंगेली को समझाईस देकर समस्या का निदान करने और बहिष्कार वापस लेकर कोर्ट में कार्य करने का निर्देश यह कहते हुए दिया कि भविष्य में ऐसी घटना नही होगी, जिसके उपरांत अधिवक्ता संघ के सदस्य ने अपने बहिष्कार वापस लेकर कुटुंब न्यायालय में पक्षकारों के हित में कार्य करना आरंभ कर दिया।

सर्विस कंपनी मॉडल सेसरकारी भवनों के सौर ऊर्जीकरण के लिए निजी निवेशकों की भागीदारी से तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। योजना में उच्च आय वर्ग की कॉलोनियों में सौर संयंत्र लगाकर बिजली बिल में बचत को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

तेजी से बढ़ते निवेश, कम लागतऔरबेहतर नीतियों से मध्यप्रदेश सौर ऊर्जा का राष्ट्रीय केंद्र बन कर उभर रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि राज्य ऊर्जा सरलस राज्य बन चुका है। राज्य सरकार प्रदेश को अक्षय ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाकर देश में नवकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति का केन्द्र बनाने के प्रयासों में जुटी हुई है। मध्यप्रदेश- भारत के %नेट जीरो कार्बन-2045 में प्रमुख योगदानकर्ता भारत के ‘नेट जीरो कार्बन’ लक्ष्य वर्ष- 2070 को प्राप्त करने में राज्य सरकार की यह पहल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मध्यप्रदेश तेजी से नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति लाने वाला राज्य बन चुका है। आने वाले वर्षों में यह न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करेगा, बल्कि अन्य राज्यों को भी ऊर्जा आपूर्ति करने में सक्षम बनेगा।

तो क्या बदल जाएगा इन शराब दुकानों का पता !

रायपुर/नवप्रदेश। सब कुछ ठीक-ठाक रहा और संबधित पंचायतों से अनापति प्रमाण पत्र (एनओसी) मिल गई तो पहले से चल रही 10 शराब दुकानों को 10 नए क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाएगा. प्रशासन ने इसके लिए प्रयास शुरु कर दिये हैं. महासमुंद्र कोलेक्टर (आकरानी) ने जिला पंचायत सीईओ को पत्र लिखकर संबधित पंचायतों से यथाशीघ्र अनापति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने कहा है नई आबकारी 2025-26 के तहत नई शराब दुकान खोली जायेगी. तथा पुरानी दुकानों को ऐसी जगह शिफ्ट किया जाएगा जहाँ दूर-दूर तक शराब दुकान नहीं हने से उस क्षेत्र में तस्करी के जरिये शराब पहुंचाई जाती है. इससे शराब की तस्करी रोकते और अन्य राज्यों से आने वाली शराब को रोकने में मदद मिल सकेगी. साथ शासन के राजस्व में बढ़ोतरी भी होगी. तत्संबंध में कोलेक्टर को 1 अप्रैल 2025 से पहले आयुक्त आबकारी को प्रस्ताव भेजना होगा. महासमुंद्र जिले की बेमगा नई महासमुंद्र की देशी मदिरा दुकान को गाम बगहनी, देशी मदिरा दुकान झलप को रायतूम, देशी मदिरा दुकान कोमराखान को गाम खट्टी, देशी मदिरा दुकान शीथरी को गाम तेंदुकोनी, देशी मदिरा दुकान सरायपाली को गाम बिरकोल आदि प्रस्तावित गांव का नाम होगा.

%जुग-जुग जिये बिहार' = स्थापना...

शुभकामनाएं। भारतीय इतिहास को गौरवान्वित करने वाला हमारा यह प्रदेश आज अपनी विकास यात्रा के जिस महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, उसमें यहां के परिश्रमी और प्रतिभाशाली बिहारवासियों की अहम भागीदारी है। हमारी संस्कृति और परंपरा के केंद्र-बिंदु रहे अपने इस राज्य के चौरफाा विकास के लिए हम को कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे।=

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, =संस्कृति, ज्ञान और सभ्यता की महान धरा बिहार के स्थायी नागरिक अपने सामर्थ्य से राष्ट्र और समाज के उजयन में भूमिका निभाते रहें।

श्री शाह ने लिखा, सभी बिहारवासियों को %बिहार जावन’ की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्ञान, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत की भूमि बिहार ने हमेशा देश को नेतृत्व और नई ऊर्जा प्रदान की है। इतिहास

न्यूज गैलरी

विकास दर में 100 प्रतिशत की वृद्धि ने दुनिया को चौंकाया

नई दिल्ली। भारत ने बीते एक दशक में अपनी अर्थव्यवस्था को दोगुना कर दुनिया को चौंका दिया है। आईएमएफ के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, भारत की GDP 2015 में 2.1 ट्रिलियन थी, जो 2025 तक बढ़कर 4.3 ट्रिलियन हो गई। भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर आईएमएफ के हवाले से यह दावा किया है। भारत ने बीते एक दशक में अपनी अर्थव्यवस्था को दोगुना कर दुनिया को चौंका दिया है। आईएमएफ के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, भारत की GDP 2015 में 2.1 ट्रिलियन थी, जो 2025 तक बढ़कर 4.3 ट्रिलियन हो गई। यह 105व की वृद्धि दर को दर्शाता है, जो अमेरिका (66व) और चीन (76व) जैसे वैश्विक दिग्गजों से भी तेज है। भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर आईएमएफ के हवाले से यह आंकड़ा साझा कर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस उपलब्धि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व और उनकी सरकार की सक्रिय आर्थिक नीतियों का परिणाम बताया। उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, “यह उपलब्धि स्वतंत्रता के बाद से किसी भी पिछली सरकार को नहीं मिली थी। मोदी सरकार के साहसिक सुधार और व्यापार सुगमता को ध्यान देने से भारत वैश्विक महाशक्तियों को पीछे छोड़ रहा है।

बैंक कर्ज 11 फीसदी बढ़ा, जमा में 10 प्रतिशत उछाल; अब महिंद्रा के वाहन भी 3 फीसदी तक होंगे महंगे



बिजनेस डेस्क। बैंकों का कर्ज 7 मार्च को समाप्त पखवाड़े तक सालाना आधार पर 11.1 फीसदी की वृद्धि के साथ 7225.10 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया।इस अवधि तक बैंकों में जमा राशि 10.2 फीसदी बढ़कर 181.28 लाख करोड़ रुपये पहुंच गई। आरबीआई के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, मूल्य के लिहाज से देखों तो 7 मार्च को समाप्त पखवाड़े में बैंक कर्ज 1.38 लाख करोड़ रुपये बढ़ा है, जबकि जमा राशि में 2.25 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गई?है। बैंकिंग क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि नकदी की कमी और जमा राशि जुटाने के दबाव के कारण बैंक आक्रामक तरीके से कर्ज देने से बच रहे हैं। निजी क्षेत्र के कई?बड़े बैंक अपने कर्ज-जमा अनुपात को घटाने पर ध्यान दे रहे हैं। इस कारण?पिछले कुछ?महीनों में कर्ज वृद्धि की रफ्तार घटी है।हालांकि, आरबीआई के तरलता कवरेज अनुपात ढांचा और एनबीएफसी पर बड़े जोरिखम भार को वापस लेने जैसे कदमों से आने वाले महीनों में बैंकों के कर्ज बांटने की रफ्तार बढ़ सकती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा भी अप्रैल से एसयूवी व वाणिज्यिक वाहनों की कीमतों में तीन फीसदी तक बढ़ोतरी करेगी। कंपनी ने कहा, बढ़ती उत्पादन लागत और जिसों की कीमतों में वृद्धि से यह फैसला लिया गया है। मारुति समेत कई?कंपनियां भी दाम बढ़ाने की घोषणा कर चुकी हैं। बाजार नियामक सेबी ने पिछले साल ‘फिन-इन्स्युएंसर’ ढांचे के लागू होने के बाद से सोशल मीडिया मंचों से 70,000 भ्रामक खाते और पोस्ट हटाए हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) के पूर्णकालिक सदस्य अनंत नारायण जी ने शुक्रवार को कहा, अपंजीकृत निवेश सलाहकार और शोध विश्लेषक एक खतरा हैं, जो निवेश में लोगों की बढ़ती रुचि का फायदा उठा रहे हैं। ऐसे सलाहकारों से लोगों को बचाने के प्रयासों के तहत अक्टूबर, 2024 से अब तक सेबी ने 70,000 से अधिक ‘भ्रामक खातों और पोस्ट को हटाने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों के साथ काम किया है। पंजीकृत निवेश सलाहकारों के कार्यक्रम में अनंत नारायण ने बेहतर अनुपातन सुनिश्चित करने में सलाहकारों की मदद मांगी। साथ ही, सेबी पंजीकृत संस्थाओं की पहचान में मदद के लिए यूपीआई ‘पेराइट’ खाते और इस दिशा में नियामक के प्रयासों के रूप में वैकल्पिक केंद्रीकृत शुल्क संग्रह तंत्र का उल्लेख किया।

2025 तक 150 अरब डॉलर के हमारे शुरुआती लक्ष्य से कहीं अधिक है

भारत की बायोइकोनॉमी बीते 10 वर्षों में 16 गुना बढ़कर 165.7 अरब डॉलर हुई : केंद्रीय मंत्री

नई दिल्ली। भारत की बायोइकोनॉमी में बीते 10 वर्षों में 16 गुना का इजाफा हुआ है और यह 2024 में बढ़कर 165.7 अरब डॉलर की हो गई है, जो कि 2014 में 10 अरब डॉलर थी। यह जानकारी सरकार द्वारा शुक्रवार को दी गई। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय राजधानी में बीआईआरएसी के स्थापना दिवस समारोह में कहा कि यह तेज वृद्धि भारत के भविष्य के आर्थिक विकास के प्रमुख स्तंभ के रूप में बायोटेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

डॉ सिंह ने ‘आईबीईआर 2025’ रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, “केवल 10 वर्षों में भारत की बायो-इकोनॉमी 10 अरब डॉलर से बढ़कर 165.7 अरब डॉलर हो गई है, जो 2025 तक 150 अरब डॉलर के हमारे शुरुआती लक्ष्य से कहीं अधिक है।”



रिपोर्ट में कहा गया कि यह सेक्टर कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 4.25 प्रतिशत का योगदान दे रहा है। पिछले चार

वर्षों में इस सेक्टर ने 17.9 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दिखाई है, जो वैश्विक बायोटेक पावरहाउस के

उद्देश्य बायोटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देना है।केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह पहल इनोवेशन को बढ़ावा देकर, उद्योग-अकादमिक सहयोग को बढ़ाकर और भारतीय स्टार्टअप को वैश्विक सफलता के लिए तैयार करके भारत के बायोटेक इकोसिस्टम को मजबूत करेगी।इस पहल के तहत विदेशी विशेषज्ञों, विशेषकर भारतीय प्रवासियों को इंटरनेशनल मेंटर के रूप में शामिल किया जाएगा, जो समाज को योगदान देने के लिए स्वेच्छे से आगे आएंगे।केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में स्वीकृत बायो-ई3 पॉलिसी के बारे में भी बताया, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में रिसर्च, इनोवेशन और उद्यमिता को गति देना है।पिछले दशक में आरएंडडी पर भारत का कुल व्यय दोगुने से अधिक होकर 2013-14 में 60,196 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024 में 1,27,381 करोड़ रुपये हो गया है।

भारत के आईटी उद्योग में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) शामिल है

ट्रंप के शुल्क से भारतीय आईटी क्षेत्र में मंदी की आशंका, लाखों नौकरियां खतरे में

जयपुर। भारत का आईटी उद्योग, जो अर्थव्यवस्था, रोजगार और निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अमेरिका द्वारा संभावित शुल्क के प्रभाव के लिए तैयार हो रहा है। भारत के आईटी उद्योग में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) शामिल है। बीपीओ सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं (आईटीईएस) उद्योग का हिस्सा है और भारत इस क्षेत्र में अग्रणी है। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) का अर्थ है कंपनी के कार्यों के एक हिस्से को किसी तीसरे पक्ष को आउटसोर्स करना। बीपीओ को उप-अनुबंध भी कहा जाता है। इसका उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि ग्राहक सेवा, पेरोल, बिलिंग, बीमा दावा प्रसंस्करण, आदि। बीपीओ का उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है, जैसे कि विनिर्माण, ई-कॉमर्स, स्वास्थ्य सेवा और वित्त। व्यापार अनुमानों के अनुसार, सूचना प्रौद्योगिकी और बिजनेस प्रोसेस



मैनेजमेंट (आईटी-बीपीएम) क्षेत्र ने देश के 4.27 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 7.5 प्रतिशत का योगदान दिया। ट्रम्प ने पहले ही भारत के इस्पात और एल्यूमीनियम उद्योग पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाया है और अमेरिकी राष्ट्रपति 2 अप्रैल से अधिक वस्तुओं और वस्तुओं पर शुल्क लगाने की संभावना बढ़ रही है। यदि शुल्क मंदी के साथ गहरा होता है, तो भारत के सबसे तेजी से बढ़ते व्यवसाय पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अमेरिका द्वारा शुल्क लगाने की बात कही है। उनके

सबसे अधिक प्रभावित होगा। भारत के कुल निर्यात में आईटी उत्पादों और इंजीनियरिंग वस्तुओं की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। ऐसी स्थिति में, शुल्क के कारण आईटी क्षेत्र की वृद्धि लगभग नीचे चली जाएगी, डाटा ने कहा। भारत का आईटी उद्योग हर साल 280 अरब डॉलर से अधिक का निर्यात करता है। साथ ही, यह देश में लाखों लोगों के लिए रोजगार भी पैदा करता है। व्यापार अनुमानों के अनुसार, दक्षिण एशियाई देश में उद्योग में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 54 लाख से अधिक लोग कार्यरत हैं। डाटा ने आगे कहा, भारत के आईटी उद्योग के निर्यात आदेशों का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 50-55 प्रतिशत, अमेरिका से आता है। ऐसी स्थिति में, यदि ट्रम्प की शुल्क नीति लागू की जाती है, तो यह भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों की लागत में वृद्धि करेगा। इससे इस क्षेत्र के निर्यात पर असर पड़ेगा। और नौकरियों में भी मुश्किलें आएंगी।

सेबी ने भ्रामक सोशल मीडिया कंटेंट पर कसी नकेल, हटाई 70,000 पोस्ट

मुंबई। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने जानकारी दी कि सोशल मीडिया पर मिसलीडिंग कंटेंट (भ्रामक सामग्री) के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है, सेबी की ओर से अक्टूबर 2024 से 70,000 से अधिक पोस्ट और अकाउंट को हटया गया है। सेबी द्वारा यह कदम गलत सूचनाओं से निपटने और ऑनलाइन फाइनेंशियल इन्फ्यूएंस को रेगुलेट करने की कड़ी में उठाया गया है। बाजार नियामक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि वह यह सुनिश्चित कर सके कि इस तरह का कोई भी कंटेंट किसी भी निवेशक को प्रमित न करे। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य अनंत नारायण ने एसोसिएशन ऑफ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स (एआरआईई) शिखर समेलन में सेबी के इन प्रयासों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, हम सभी के लिए एक आम चिंता अनरजिस्टर्ड निवेश सलाहकारों/शोध विश्लेषकों

से जुड़ी है, जो निवेश में बढ़ती रुचि का गलत फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेबी के प्रपोजल के तहत यूपीआई ‘पेराइट’ हैंडल का इस्तेमाल निवेशकों को रजिस्टर्ड संस्थाओं की आसानी से पहचान करने में मदद करेगा, ताकि वे खुद को धोखेबाजों से बचा सकें।नारायण ने कहा, निवेश में बढ़ती रुचि के साथ ही अनरजिस्टर्ड निवेश सलाहकारों और शोध विश्लेषकों की संख्या में भी तेजी से वृद्धि हुई है। ये निवेश सलाहकार और शोध विश्लेषक निवेशकों को गुमराह करते हैं।नारायण ने यह भी घोषणा की कि सेबी निवेशकों के व्यवहार को बेहतर ढंग से समझने और अपनी आउटरीच रणनीतियों में सुधार करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सर्वे की योजना बना रहा है। विदेशी निवेश पर नारायण ने कहा, ग्लोबल डेट इंड्रइसेस में भारत के शामिल होने से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) अग्र प्रवाह में वृद्धि दर्ज की है।

इंडियन ऑयल ने जेल के कैदियों और सुधार गृहों के लिए अपनी परिवर्तनकारी पहलों का विस्तार किया



हरिद्वार। इंडियन ऑयल के चेयरमैन श्री ए एस साहनी ने आज राज्य सरकार और जेल अधिकारियों की मौजूदगी में भारत के विभिन्न स्थानों पर इंडियन ऑयल के ‘परिवर्तन - जेल से गौरव’ के 10वें चरण और ‘नई दिशा - भविष्य को पिर से परिभाषित करना’ के 7वें चरण का शुभारंभ किया।

इंडियन ऑयल द्वारा क्रमशः 15 अगस्त, 2021 और 26 जनवरी, 2023 को शुरू की गई दोनों पहलों का उद्देश्य खेलों की शक्ति के माध्यम से जेलों और सुधार गृहों में बंद कैदियों के जीवन को बदलना है। नए चरण में, इंडियन ऑयल 22 जेलों और

कैदियों में अनुशासन, उद्देश्य और आशा की भावना पैदा करने की उमीद करते हैं ताकि वे सम्मान के साथ समाज में शामिल हो सकें।- इस अवसर पर, भाग लेने वाले राज्य सरकार के अधिकारियों और जेल अधिकारियों ने इस अनूठी पहल के लिए इंडियनऑयल को धन्यवाद दिया, जो सुधार गृहों में कैदियों और बच्चों को बेहतर जीवन बनाने और समाज में उपयोगी योगदान देने में मदद करेगी। शुरुआत से ही, इस पहल ने भाग लेने से लाभार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से दिशा देने का अवसर मिल रहा है। अपने छोटे से प्रयास के माध्यम से, हम

खेल

एक बार फिर दमदार नजर आ रही है मुंबई इंडियंस

नई दिल्ली। मुंबई इंडियंस की टीम चेन्नई सुपर किंग्स के साथ इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की सबसे सफल टीम में शामिल है। हालांकि पिछले कुछ सीजन मुंबई इंडियंस के लिए बहुत अच्छे नहीं रहे हैं और पिछले सीजन में तो उनके लिए रोहित शर्मा को हटाने का फैसला भी फैसले के गले पूरी तरह से नहीं उतरा था। इसका प्रभाव कहीं न कहीं टीम के मनोबल पर भी पड़ा। लेकिन आईपीएल 2025 में एमआई पुरानी अस्थिरता को पीछे छोड़कर एक दमदार सीजन के लिए तैयार नजर आ रही है।पिछले चार सीजन में दो बार अंक तालिका में सबसे निचले पायदान पर नजर आने वाली एमआई इस बार कप्तान हार्दिक पांड्या के साथ कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरपूर है। हार्दिक इस दौरान दो बार आईसीसी प्रतियोगिताओं में महत्वपूर्ण प्रदर्शन कर चुके हैं। टी20 विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी में भारत हार्दिक

पांड्या के अहम रोल और रोहित शर्मा की कप्तानी में विजयी बना है। हार्दिक के साथ रोहित एमआई लीडशिप का अहम हिस्सा हैं। फैस में हार्दिक की स्वीकार्यता बढ़ी है और टीम ने नीलामी में जो खिलाड़ी रिटेन किए हैं, उससे पता चलता है कि एमआई के कोर रूप में हार्दिक पांड्या की कप्तानी को लेकर सहजता है।एमआई ने इस बार नीलामी में ट्रेट बोल्ट को लेकर जसप्रीत बुमराह के साथ बेहतरीन पेस अटैक बनाया है। अगर पिछले दो सीजन में इन दोनों गेंदबाजों का पावरप्ले इकोनमी रेट केवल 6.5 का रहा है, जो दिखाता है कि दोनों की जोड़ी कितनी जबरदस्त साबित हो सकती है। बल्लेबाजी की बात करें तो रोहित शर्मा, तिलक वर्मा और सूर्यकुमार यादव जैसे तूफानी बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट संयुक्त तौर पर 150.62 का रहा है।दीपक चाहर भी इस बार मुंबई इंडियंस के पेस अटैक खेमे में शामिल है। स्पिन डिपार्टमेंट में मिशेल



सैंटरन, मुजीब उर रहमान और करन शर्मा हैं। हालांकि स्पिन में सैंटरन के अलावा किसी और अनुभवी स्पिनर का न होना टीम की कमजोर कड़ी साबित हो सकता है। अगर सैंटरन परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो टीम के बाकी स्पिनरों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी और यह स्पिन अटैक अभी युवा है। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह की फिटनेस मुंबई इंडियंस के लिए एक बड़ा सवाल है। बुमराह की पूरे सीजन में उपलब्धता एमआई की

गेंदबाजी की दिशा को तय करेगी। युवा ओवरसीज बल्लेबाजों की बात करें तो विल जैक्स, बेवॉन जैकब्स और रयान रिकेल्टन बड़े हितर हैं। रोहित शर्मा की टॉप फार्म और हार्दिक पांड्या का धुआंधार ऑलराउंड प्रदर्शन इस बार टीम के बेहतर प्रदर्शन का वादा करता है। मुंबई इंडियंस का घरेलू मैदान

आईपीएल 2025 : खिलाड़ियों की बदमिजाजी नहीं होगी बर्दाश्त, आईपीएल में 5 मैचों के लिए लग सकता है बैन

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के आगामी सीजन से पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने खिलाड़ियों और टीमों के लिए नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन बदलावों में सबसे प्रमुख है स्लो ओवर रेट के लिए कप्तानों पर लगने वाले बैन को हटाना। बीसीसीआई ने इसकी जगह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की तरह डिमेरिट पॉइंट सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया है। हालांकि, यह डिमेरिट पॉइंट सिस्टम केवल स्लो ओवर रेट तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे पूरे कोड ऑफ कंडक्ट में शामिल किया गया है। इसके तहत खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ को भी नियमों का उल्लंघन करने पर डिमेरिट पॉइंट मिलेगे, जिसके आधार पर उन पर 5 मैचों तक का प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 22 मार्च से शुरू हो रहे आईपीएल 2025 सीजन से पहले मुंबई में बीसीसीआई अधिकारियों ने



सभी 10 फ्रेंचाइजी के कप्तानों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में कप्तानों को कोड ऑफ कंडक्ट में किए गए इन महत्वपूर्ण बदलावों की जानकारी दी गई। यह नए नियम इस सीजन से ही लागू होंगे और प्लेइंग कॉडिशंस का हिस्सा होंगे। अभी तक आईपीएल में खिलाड़ियों द्वारा किसी भी तरह की बदसलूकी या गलत व्यवहार करने पर मैच रेफरी द्वारा जुर्माना लगाया जाता था। लेकिन अब खिलाड़ियों को जुर्माने के साथ-साथ डिमेरिट पॉइंट भी मिलेंगे, जो उनके लिए प्रतिबंध का कारण बन सकते हैं। क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, अब किसी भी खिलाड़ी या टीम द्वारा कोड ऑफ कंडक्ट का

उल्लंघन करने पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की तरह डिमेरिट पॉइंट दिए जाएंगे। यह डिमेरिट पॉइंट खिलाड़ी या टीम के खाते में पूरे 36 महीने यानी 3 साल तक बने रहेंगे और इसी के आधार पर सजा निर्धारित की जाएगी। नए नियमों के अनुसार, यदि कोई खिलाड़ी लेवल-1 के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, तो उस पर मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना और 1 डिमेरिट पॉइंट लगाया जा सकता है। लेवल-2 के उल्लंघन पर 3 से 4 डिमेरिट पॉइंट जुड़ेंगे। वहीं, लेवल-3 के उल्लंघन के लिए 5 से 6 डिमेरिट पॉइंट और लेवल-4 के उल्लंघन के लिए 7 से 8 डिमेरिट पॉइंट दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि कितने डिमेरिट पॉइंट पर खिलाड़ी को कितनी सजा मिलेगी। कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 7.6 के अनुसार, यदि किसी खिलाड़ी के खाते में 4 से 7 डिमेरिट पॉइंट जुड़ते हैं, तो उसे एक मैच के लिए निलंबित किया जाएगा।



पूर्व केन्द्रीय मंत्री बोले-राहुल गांधी माओवादियों के प्रभाव में

इंदौर में रविशंकर प्रसाद ने जजों पर कहा- बेटियों को लेकर संवेदनशील रहें

इंदौर/नवप्रदेश। इंदौर आए पूर्व केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एक बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे किस मेरिट के आधार पर नेता बने हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते, वे माओवादियों के प्रभाव में हैं। दरअसल, एक इंटरव्यू में राहुल गांधी ने कहा था कि मेरिट एक पूरी तरह से दोषपूर्ण अवधारणा है।

पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज की टिप्पणी को लेकर कहा कि न्यायाधीश बेटी और बच्ची के बारे में संवेदनशील बनें। रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को केंद्र

सरकार के बजट पर लोगों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के अनुसार देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

उन्होंने इंदौर की आर्थिक प्रगति की सराहना करते हुए कहा- इंदौर देश के शीर्ष शहरों में शामिल है और यहां की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है।

बेटियों के प्रति संवेदनशील बनें न्यायमूर्ति

एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज की टिप्पणी पर पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि जब बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की बात होती है तो न्यायमूर्तियों का भी काम है कि बेटियों के बारे में संवेधनशील रहें।

दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट के



जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने अपने एक फैसले में कहा था कि आरोपियों ने महिला का प्राइवेट पार्ट पक?। और उसके कपड़े उतारने की कोशिश की, लेकिन यह बलात्कार की कोशिश नहीं मानी जा सकती। बलात्कार की कोशिश साबित करने के लिए स्पष्ट इरादा दिखना चाहिए। तथ्यों के आधार

पर यह सिर्फ वस्त्र उतारने के इरादे से हमले (आईपीसी की धारा 354) का मामला बनता है, बलात्कार का नहीं।

कर्नाटक सरकार ने ओबीसी वर्ग के अधिकार को नुकसान पहुंचाया

रविशंकर प्रसाद ने कर्नाटक सरकार

के मुस्लिम कॉन्वेंटर्स को सरकारी टेंडर में 4व्न आरक्षण देने के फैसले की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि इसमें ओबीसी वर्ग के अधिकार को नुकसान पहुंचाया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उपासना पद्धति के आधार पर आरक्षण देना सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ है।

इन मुद्दों पर भी बोले- रविशंकर प्रसाद

1. **औरंगजेब के किले के सामने शिवाजी का स्मारक**
रविशंकर प्रसाद ने औरंगजेब के मकबरे के सामने शिवाजी महाराज का स्मारक बनाने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले की सराहना की। कहा कि %अगर औरंगजेब भारत के इतिहास का हिस्सा है, तो शिवाजी भी विरासत के

रूप में उनकी तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। रविशंकर प्रसाद ने भारत और पाकिस्तान के बीच एक क्रिकेट मैच का जिक्र करते हुए बताया कि जब भारत के मुस्लिम क्रिकेटर जहीर खान और इरफान पठान लाहौर में पाकिस्तान के खिलाड़ियों को गेंदबाजी कर रहे थे, तब वहां के बिदेश मंत्री ने उनसे पूछा कि %ये मुस्लिम खिलाड़ी हैं?% इस पर मैंने जवाब दिया, ये भारत माता के बेटे हैं, जो भारत को जीत दिलाने आए हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की सोच है।

2. **स्वतंत्रता सेनानियों को लेकर निष्पक्ष फिल्में नहीं बनती**
पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने ऐतिहासिक संदर्भों का उल्लेख करते हुए कहा, %देश को यह स्वीकार नहीं करना चाहिए कि औरंगजेब की विरासत को सम्मान दिया जाए। हमेशा छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान सर्वोपरि रहेगा।% स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को लेकर निष्पक्ष फिल्में क्यों नहीं बनाई जाती। भगत सिंह को सही तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, और संभाजी महाराज के साथ जो अन्याय हुआ, वह देश को जानने का अधिकार है।

3. तीन तलाक और संविधान का जिक्र

न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर बोलते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा, %देश की न्यायपालिका स्वतंत्र है और हम इसका पूरा सम्मान करते हैं। न्यायिक प्रक्रियाओं में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए।% तीन तलाक कानून पर कहा, %तीन तलाक को पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में नियंत्रित कर दिया गया, लेकिन भारत में इसे राजनीतिक कारणों से टाला जाता रहा। जब हमारी सरकार ने इसे समाप्त किया, तब भी विरोध किया गया।%

संक्षिप्त खबरें

लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए चुनाव अधिकारियों के साथ बैठकों में शामिल होकर उठाएं लाभ

भोपाल/नवप्रदेश। निर्वाचन प्रक्रिया को सशक्त बनाने और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान केंद्र स्तर पर लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर देशभर में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के साथ सीईओ, डीईओ और ईआरओ स्तर पर बैठकों की जा रही है। पूरे देश में प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, जिले और राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली बैठकें 31 मार्च, 2025 तक पूरी कर ली जाएंगी। आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों से लंबित प्रकरणों का नियमानुसार निराकरण के लिए चुनाव अधिकारियों के साथ बैठकों में शामिल होकर जमीनी स्तर की भागीदारी का सक्रियतापूर्वक लाभ उठाने की अपील की है। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार द्वारा सभी 28 राज्यों और 8 संघ राज्य-क्षेत्रों के सभी 788 जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) और 36 सीईओ को राज्य, जिला एवं क्षेत्र स्तर पर बैठकर कर लंबित प्रकरणों का समाधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 में निर्धारित कानूनी ढांचे और आयोग द्वारा समय-समय पर जारी मैनुअल, दिशा-निर्देशों और अनुदेशों के भीतर करने के निर्देश दिए गए थे। भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दलों और उनके अधिकृत प्रतिनिधियों जैसे बृथ लेवल एजेंटों (बीएलए), पोलिंग एजेंटों, कार्डेंटिंग एजेंटों और चुनाव एजेंटों की चुनाव संचालन सहित विभिन्न चुनावी प्रक्रियाओं में विशिष्ट भूमिकाएं होती हैं। इसके साथ ही आयोग ने विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, जिलों प्रदेश स्तर पर आयोजित बैठकों में सक्रिय रूप से और उत्साहपूर्वक शामिल होने पर राजनीतिक दलों द्वारा जमीनी स्तर पर उनकी इस प्रकार की भागीदारी का स्वागत किया गया है।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर देशभर में आयोजित होने वाली राजनीतिक दलों के साथ बैठकों की तस्वीर आयोग के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल (एक्स) **संक्षिप्तसंक्षिप्त**धक्कर पर तस्वीरें देखी जा सकती हैं।

परिवहन विभाग में अधिकारियों के ट्रांसफर, नौ क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारी इधर से उधर

भोपाल/नवप्रदेश।मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के क्षेत्रीय/ अतिरिक्त क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारियों के ट्रांसफर आदेश जारी किए गए हैं। इसमें 9 अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। परिवहन विभाग की तरफ से जारी आदेश के अनुसार नरसिंहपुर के जिला परिवहन अधिकारी जितेंद्र कुमार शर्मा को प्रभारी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी भोपाल बनाया गया है। वहीं, प्रभारी अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी छतरपुर विक्रमजीत सिंह कंग को प्रभारी क्षेत्रीय अधिकारी ग्वालियर, प्रभारी अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी छिंदवाड़ा मनोज कुमार को प्रभारी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सागर, सागर के प्रभारी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सुनील कुमार शुक्ला को जिला परिवहन अधिकारी पन्ना, प्रभारी अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कटनी विमलेश कुमार गुप्ता को जिला परिवहन अधिकारी मण्डला, सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संभागीय उप परिवहन आयुक्त कार्यालय ग्वालियर मधु सिंह को प्रभारी अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी छतरपुर, जिला परिवहन अधिकारी दतिया स्वाति पाठक को सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, परिवहन आयुक्त कार्यालय ग्वालियर, प्रभारी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी नर्मदापुरम निशा चौहान को जिला परिवहन अधिकारी देवास और जिला परिवहन अधिकारी देवास जया बसावा को प्रभारी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी नर्मदापुरम बनाया गया है।

एमपी में डेढ़ माह में सड़क दुर्घटनाओं में 1656 मौतें, तेज रफ्तार बना बड़ा कारण

मध्य प्रदेश में पिछले डेढ़ माह में सड़क हादसों में 1656 लोगों ने अपनी जान गवा दी। इसमें 1,026 लोगों की मौत ओवरस्पीडिंग के कारण हुई।

भोपाल/नवप्रदेश। मध्य प्रदेश में पिछले डेढ़ माह में सड़क हादसों में 1656 लोगों ने जान गंवाई। वहीं, प्रयागराज महाकुंभ के दौरान एमपी बॉर्डर पर सड़क हादसों में 202 लोगों की मौत हुई। विधायक दिनेश राय मुनमुन के प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यह जानकारी दी। डॉ. मोहन यादव ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों में 144 पुरुष, 50 महिलाएं और 8 बच्चे शामिल थे। उन्होंने कहा कि राज्यभर में कुल 1,656 लोगों की सड़क हादसों में मौत हुई, जिनमें 152 लोगों ने हेलमेट न पहनने के कारण और 26 लोगों ने सीट बेल्ट न पहनने की वजह से जान गंवाई। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले डेढ़ माहने में एमपी बॉर्डर पर कुल 552 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 944 लोग घायल हुए। इस दौरान शराब पीकर गाड़ी चलाने से केवल एक हादसा



हुआ, लेकिन इसमें कोई मौत नहीं हुई। 2022 के आकड़े के अनुसार सड़क हादसों में मध्य प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है।

1,026 लोगों की मौत ओवरस्पीडिंग के कारण

मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क हादसों की सबसे बड़ी वजह तेज रफ्तार है। 1,026 लोगों की मौत ओवरस्पीडिंग के कारण हुईं, जबकि 40 लोगों की मौत ट्रेफिक नियमों के उल्लंघन की वजह से हुईं। इसके अलावा, 56 लोगों की मौत

ब्लैक स्पाॅट्स पर हुई।

सड़क सुरक्षा नियमों का पालन जरूरी

मुख्यमंत्री ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात नियमों का पालन अनिवार्य है। इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग, गति सीमा का पालन और यातायात नियमों का सही तरीके से अनुपालन करने से हादसों को रोका जा सकता है।

करोड़पति कॉन्स्टेबल केस में अब पुलिस की एंट्री

सौरभ और उसकी मां पर

एफआईआर ; अनुकंपा नियुक्ति के लिए झूठा शपथ पत्र दिया था



(शिकायत) किरन कुमार को एक जनवरी 2025 को संयुक्त परिवहन आयुक्त (प्रशासन) की ओर से एक पत्र मिला था। जिसमें सेवानिवृत्त परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा की नियुक्ति को लेकर दिए गए शपथ पत्र की जांच के निर्देश थे। सहायक परिवहन आयुक्त (शिकायत) ने जांच की और सर्विस रिकॉर्ड मंगाया। सौरभ शर्मा ने शपथ पत्र में यह जिक्र नहीं किया कि उसका बड़ा भाई सचिन शर्मा छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी में हैं। सौरभ की नियुक्ति के लिए उसकी मां उमा शर्मा ने भी शपथ पत्र दिया था। जिसमें बड़े बेटे की सरकारी नौकरी की बात छिपाई थी। जांच के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त विभाग में संपर्क किया गया और

वेबसाइट से कर्मचारियों की सूची निकाली तो वहां सौरभ के बड़े भाई सचिन शर्मा के सड़क विकास निगम रायपुर में तैनात होने की पुष्टि हुई। जिससे शपथ पत्र झूठे होने का प्रमाण मिला है।

कौन सी एजेंसी क्या जांच कर रही?

परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा केस में ईडी मनी ट्रेल और प्रॉपर्टी के दस्तावेज, तो इनकम टैक्स विभाग सौरभ के दोस्त चेतन सिंह गौर की गाड़ी से मिले 5.4 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए की जांच कर रही है। लोकयुक्त आय से ज्यादा संपत्ति की जांच तो डीआरआई इस बात की जांच कर रही है कि जो सोना मिला है, वो लोगल तरीके से लिया गया है या नहीं?काली कमाई को कॉलोनी बनाने में खपाए जाने का कनेक्शन भी जांच एजेंसियों को मिला है। अब ग्वालियर पुलिस ने सौरभ और उसकी मां उमा शर्मा पर धोखाधड़ी व अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। विधानसभा में बजट सत्र के दौरान कांग्रेस परिवहन घोटाले का मुद्दा उठा रही है। 20 मार्च को परिवहन मंत्री

राव उदय प्रताप सिंह ने इस पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था- पहले से सक्षम एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं। मुझे लगता है कि जब तक जांच का निष्कर्ष नहीं आ जाता, उसमें अलग से व्यवधान उत्पन्न करना उचित नहीं है। अनुकंपा नियुक्ति में कलेक्टर तय करता है कि अगर संबंधित विभाग में पद खाली नहीं है तो किस विभाग में नियुक्ति दी जा सकती है?इ वो सब पारदर्शी तरीके से किया गया है। अभी शिकायत के दौरान उसके शपथ पत्र दोषपूर्ण पाए गए हैं। उसमें हमने पुलिस विभाग को लिखा है कि आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए और कार्रवाई की जाए।

सौरभ शर्मा दिसंबर 2024 में तब चर्चा में आया था, जब लोकयुक्त, ईडी और आयकर विभाग ने उसके ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की थी। इसी दौरान भोपाल के मंडोरी में इनोवा कार से 11 करोड़ रुपए कैश और 52 किलो गोल्ड जब्त किए गए थे। इसका लिंक भी सौरभ से जुड़ा था। इसके बाद सौरभ और उसके सहयोगियों की बेशुमार संपत्ति सामने आई थी।

हॉटलाइन मंटेनेन्स करने वाले कर्मियों का भत्ता हुआ दोगुना

भोपाल/नवप्रदेश। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के निर्देश पर मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी (एम.पी. ट्रांसको) में एकस्ट्रा हाईटेंशन लाइनों एवं सब-स्टेशनों का हॉटलाइन पद्धति से बिना शट-डाउन लिये मंटेनेन्स जॉब/ऑपरेशन करने वाले कर्मियों के भत्ते में भी दोगुनी बढ़ोतरी की गई है। साथ ही प्रति ऑपरेशन के लिये दिये जाने वाले भत्ते में भी दोगुनी वृद्धि कर दी गई है। भत्ता अब दोगुना मिलेगा। पहले यह 6 रुपये से 40 रुपये के मध्य मिलता था, अब यह 12 रुपये से 80 रुपये तक प्रति जॉब/ऑपरेशन के हिसाब से मिलेगा। हॉटलाइन पद्धति का माध्यम से बिना शट-डाउन लिये एकस्ट्रा हाईटेंशन लाइनों का मंटेनेन्स जॉब करने के लिये कार्मिक की सहमति आवश्यक होती है। एम.पी. ट्रांसको द्वारा उन कार्मिकों को बैंगलुरु के केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से प्रशिक्षण दिलवाने के बाद ही वह जॉब/ऑपरेशन के लिये पात्र होता है। जॉब/हॉटलाइन ऑपरेशन अत्यंत जोखिम भरा होने के कारण कार्मिकों को यह भत्ता दिया जाता है।

हादसा...

जबलपुर में तार की चपेट में आए; ग्रामीणों का आरोप- शिकायत के बावजूद नहीं हटाई लाइन

करंट लगने से भाई-बहन की मौत, एक गंभीर

जबलपुर/नवप्रदेश। जबलपुर में सगे भाई-बहन की करंट लगने से मौत हो गई। एक अन्य बच्चा झुलस गया है, उसकी हालत गंभीर है। तीनों बच्चे खेत के आसपास घूम रहे जानवरों को भगाने गए थे। इसी दौरान खेत के किनारे झूल रहे बिजली के तार की चपेट में आ गए।

घटना सुरैया टोला गांव में आज शनिवार सुबह करीब 8 बजे की है। बच्चों के माता-पिता खेत में काम कर रहे थे। फसल के पास जानवर घूम रहे थे, जिन्हें भगाने के लिए देव (12) अपनी बहन पूजा (10) और दिलीप (12) के साथ खेत किनारे दौड़कर गया।

खंभे से झूलता बिजली का तार जमीन पर पड़ा था, जिसकी चपेट में बच्चे आ गए।

पाटन स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद दिलीप को जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। ग्रामीणों ने शवों को पाटन-शहपुरा रोड पर रखकर चक्काजाम कर दिया। उनका आरोप है कि बिजली विभाग ने शिकायत के बाद भी तार नहीं हटाए। उन्होंने पाटन में पदस्त्री जेई और लाइनमैन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

पाटन थाना पुलिस और एसडीएम के आश्वासन के बाद ग्रामीण शवों को अंतिम संस्कार के



लिए गए।

परिजन को 4-4 लाख की सहायता राशि

जिला प्रशासन के निर्देश पर बिजली विभाग की ओर से मृत

भी दिए गए हैं।

ग्रामीणों ने एमपीईबी में की थी शिकायत

जानकारी के मुताबिक, दो दिन पहले ग्रामीणों ने खेत के किनारे बिजली का तार जमीन पर पड़े होने की सूचना एमपीईबी को दी थी। बिजली विभाग की तरफ से लाइन बंद कर तार ठीक करने का आश्वासन दिया जा रहा था। सुरैया टोला गांव में रहने वाले कुछ ग्रामीणों ने शुक्रवार शाम को भी बिजली विभाग के दफ्तर में जाकर तार को ठीक करने के लिए कहा था। विभाग के कर्मचारियों ने शनिवार को मौके पर जाकर तार

सही करने की बात कही थी और आज सुबह यह हादसा हो गया।

कर्मचारी अधूरा काम छोड़ जाते हैं

पाटन एसडीएम मानवेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और पीडित परिवार को कार्रवाई का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने एसडीएम को बताया कि इससे पहले भी बिजली विभाग के कर्मचारी अधूरा काम छोड़कर गए हैं, जिसके चलते जानवर बिजली के तार की चपेट में आ चुके हैं। एसडीएम ने घटना की जानकारी जबलपुर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना और बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को दी है।